RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

दाँव पर सब कुछ लगा है रुक नहीं सकते, हम टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते...!

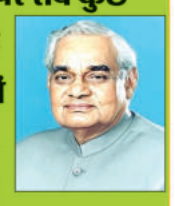

अटल बिहारी वाजपेयी

वर्ष-08, अंक - 32 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 28 मई 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

राजनीति में हिम्मत... और हिम्मत की राजनीति...

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आम जनता से जोरदार अभिनंदन करने में ही व्यस्त है और उन्ही के राज्य में पूर्व मंत्री तक कि नहीं सुनी जा रही है। उन्हें भी अपनी वाजिब मांगों को लेकर धरने पर बैठना पड़ रहा है। ऐसे में आम आदमी की इस सरकार में किस प्रकार की सुनवाई हो रही होगी इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। ऐसे में कई राजनीतिक पंडितों का कहना है कि, प्रदेश में ऐसे कई हिम्मत कोठारी जैसे नेता है जो अपनी ही सरकार की कार्य शैली से खुश नहीं है लेकिन वे ऐसी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं जैसी हिम्मत रतलाम जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता व पुर्व गृहमंत्री हिम्मत कोठारी ने दिखलाई है।

दरअसल रतलाम जिले में एक वरिष्ठ नेता के कब्जे में अवैध प्लाट था और उस प्लाट पर वास्तविक भू-स्वामी को कब्जा दिलाने के लिए एक समय भाजपा सरकार में नंबर दो की स्थिति में रहे पूर्व गृहमंत्री हिम्मत कोठारी ने कई बार प्रयास किया लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। अपनी ही सरकार में अधिकारियों की इस कार्य प्रणाली से नाराज होकर वरिष्ठ भाजपा नेता धरने पर बैठ गए जिसके बाद पूरा प्रशासन हिल गया और धरने की गूंज भोपाल तक पहुंच गई। ताबड़तोड़ रतलाम जिला पुलिस अधीक्षक पूर्व गृहमंत्री से मिलने पहुंचे और उन्हें आश्वासन देकर अपने ऑफिस में ले गए और पूरे

हिम्मत कोठारी की हिम्मत की गूंज पहुची भोपाल तक।

प्रकरण की वस्तु स्थिति जानकर तुरंत उचित कार्रवाई के निर्देश अपने अधीनस्थों को दिए। जिसके बाद पूरा महकमा हरकत में आ गया और तत्काल कार्यवाही की गई।

ऐसे में आम जनता के मन में एक ही प्रश्न है कि, प्रशासन इस पूरे प्रकरण में पूर्व गृहमंत्री के धरने के पूर्व ही ये सब कार्रवाई कर सकता था। लेकिन प्रशासन ने पूरे मामले को जानबूझकर उलझाए रखा। ऐसे कई मामले है जो प्रशासन ने उलझा रखे हैं और उन मामलों को सामने लाने के लिए कई हिम्मत कोठारी चाहिए जो अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ इतनी मूखरता से अपनी बात रख सके। लेकिन उसके लिए नेताओं में हिम्मत होना चाहिए जो शायद वर्तमान दौर के नेताओं में नहीं है। पूरे प्रदेश में अंदर ही अंदर कई नेताओं में छटपटाहट तो है लेकिन वह खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत कोठारी जैसी हिम्मत... की राजनीति चाहिए।

कई राजनीति पंडितों का मानना है कि, भाजपा सरकार में कई वरिष्ठ नेता अपनी अनदेखी से नाराज बताए जा रहे लेकिन सत्ता और संगठन के प्रभाव के आगे वे अपनी बातों को सार्वजनिक रूप से बता नहीं पा रहे हैं। हाल ही में आलीराजपुर जिले की प्रभारी मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री पर भी शराब माफियाओ के संरक्षण का आरोप लगाया था। लेकिन सत्ता और संगठन के प्रभुत्व के आगे यह भी मामला शांत कर दिया गया।

कुछ ऐसा ही मामला मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन में सामने आया है जहां महाकाल मंदिर के पार्किंग की भूमि को भाजपा विधायक को बेचने का आरोप है। जिसके बाद संबंधित विधायक ने सार्वजनिक रूप से प्रेसवार्ता में अपनी सफाई पेश की और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। जिसके बाद संगठन ने तत्काल हरकत में आकर डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया और मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। ऐसे ही कई मामले अन्य जिलों में भी है लेकिन सत्ता और संगठन के प्रभाव के चलते वे सामने नहीं आ पा रहे हैं शायद इन जिलों में भी किसी हिम्मतवीर की आवश्यकता है।

मंदिर से हीरे के आभूषण और सोना गायब

तिरुवनंतपुरम।

केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दुनिया के सबसे समृद्ध और रहस्यमयी मंदिरों में शामिल इस मंदिर से वैर नाम नामक एक बेहद कीमती हीरे का आभूषण पिछले छह महीनों से गायब बताया जा रहा है। इसके साथ ही भक्तों द्वारा दान किए गए करीब 78 ग्राम सोने का भी कोई स्पष्ट आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। पुलिस महानिदेशक की हालिया रिपोर्ट में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में कई गंभीर खामियों का उल्लेख किया गया है।

जानकारी के अनुसार, हीरे के इस आभूषण को कुछ समय पहले मरम्मत के लिए बाहर भेजा गया था, लेकिन उसके वापस आने का रिकॉर्ड मंदिर प्रशासन में दर्ज नहीं किया गया। इसी प्रकार मंदिर का एक पारंपरिक सोने का दीपक भी मरम्मत के नाम पर बाहर भेजा गया था, जो छह महीने बीत जाने के बाद भी वापस नहीं लौटा है। पुलिस प्रशासन ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक माना है और राज्य सरकार को सभी कीमती वस्तुओं को तत्काल उच्च सुरक्षा वाले स्ट्रॉन्ग रूम में रखने की सलाह दी है।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मंदिर के रिकॉर्ड और वास्तविक संपत्ति के बीच कई जगह अंतर पाया गया है। ऐसे में प्रशासनिक लापरवाही या आंतरिक मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। डीजीपी ने सिफारिश की है कि मंदिर में मिलने वाले दान और कीमती वस्तुओं की डिजिटल रिकॉर्डिंग अनिवार्य की जाए तथा पूरे परिसर में सख्त पुलिस निगरानी रखी जाए।

वर्तमान में मंदिर का संचालन पांच सदस्यीय प्रशासनिक समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें न्यायाधीश, त्रावणकोर शाही परिवार का प्रतिनिधि, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मार्च महीने के बाद से मंदिर में किसी पूर्णकालिक कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने की आवश्यकता है।

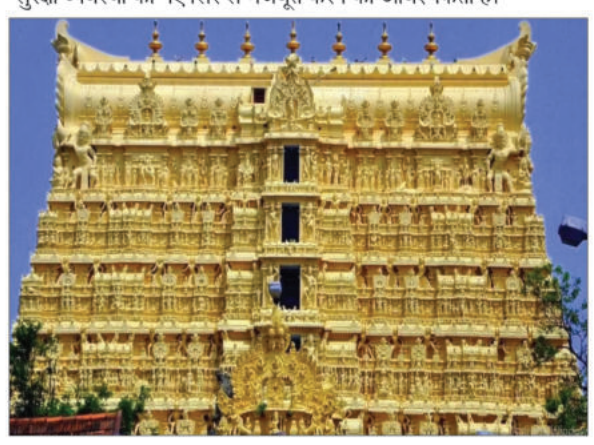

महंगाई: खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा प्रायोजित महंगाई से आम जनता परेशान है। खड़गे ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण लोगों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

खड़गे का यह बयान ऐसे समय आया है, जब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के बावजूद आम लोगों को राहत नहीं दी जा रही है। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ईंधन पर अधिक कर लगाकर जनता से अतिरिक्त वसूली कर रही है। कांग्रेस ने इसे ÷फ्यूल लूट÷ करार देते हुए कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किए हैं।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर केवल परिवहन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव रसोई, कृषि और छोटे कारोबार तक पहुंचता है। माल ढुलाई महंगी होने से रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है।

वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार आर्थिक संतुलन बनाए रखने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने

के लिए जरूरी कदम उठा रही है। महंगाई और ईंधन की कीमतों को लेकर दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। आगामी चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा आने वाले दिनों में भी राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बना रह सकता है।

नेहरूजी ने प्रगतिशील भारत निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया

नई दिल्ली, एजेंसी।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर विभिन्न नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर उन्हें याद करते हुए लिखा कि, नेहरूजी ने आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखते हुए समावेशी, सौहार्दपूर्ण और प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया।

राहुल गांधी ने शांति वन पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान कई तस्वीरें भी साझा कीं।

अपने संदेश में राहुल गांधी ने नेहरूजी के उस दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जिसमें स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक

सोच को भारत की आत्मा बताया गया था।

पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शांति वन पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर संदेश जारी कर पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी।

जिला अभी भी उम्मीदों के सहारे टिका है, देखना है कलेक्टर भरसट किस किनारे जा कर बैठते है

माही की गूंज, झाबुआ।

वैसे तो जिला हमेशा से ही अधिकारियों की फोटो छपाउ प्रवृत्ति से आहत रहा है, लेकिन हर बार जब अधिकारियों के तबादले होते है तो एक नई उम्मीद जिले की जनता में जागृत हो जाती है कि, शायद अब तो फटे पोस्टर से हीरो निकलेगा। मगर जब पोस्टर फटता है और हीरो की जगह सिर्फ फोटो छपाउ अधिकारी जिले मे आ जाते है तो जिले की जनता बे उम्मीद होती दिखाई देती है। जिले में आए ऐसे कई आईएएस अधिकारियों की फहरिस्त मौजूद है जो जिलेवासियों की उम्मीदों पर खरा ना उतरकर सिर्फ और सिर्फ खबर छपाउ और फोटो खिलाउ ही साबित हुए है। कईयों ने तो हमाम में सब नंगे की तर्ज पर जिले में खूब भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकियां लगाई है। मगर कुछ अधिकारी जिले को ऐसे भी मिले है जिन्होने अपने सिमित कार्यकाल में हीरो का रोल अदा किया है। हालांकि ऐसे अधिकारियों की फहरिस्त बहुत छोटी है। क्योंकि जिले की राजनीति पार्टियों को कभी अच्छा काम करने वाले अधिकारी पसंद ही नहीं आए और येन-केन प्रकारेण उन्हे यहां से रवानगी दिलवा दी गई। तो कई अधिकारी जिले में आकर ऐसे राजनीतिक रंग में रंगे कि तुम भी खाओ हम भी खाएं, तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहे की कहानी गढ़ कर चले गए।

अभी कुछ दिनों पहले ही जिले की कमान लंबे समय के बाद किसी पुरूष अधिकारी के हाथ में आई है। इससे पहले जिले में एक लंबे कार्यकाल तक महिला अधिकारियों की ही चर्चा रही है। जिसमें महज एकाध महिला कलेक्टर ही ऐसी रही जिनकी कार्यप्रणाली जिले वासियों को समझ में आई लेकिन वे भी जिले की राजनीतिक पार्टियों के सामने बली का बकरा बनी और जिले से रवाना हो गई। इसके अलावा जिले में आई महिला अधिकारियों में कुछके नाम ही सम्मान से लिए जाते है। मगर पिछले कार्यकाल में जिला अधिकारी के रूप में पदस्थ हुई कलेक्टर नेहा मीणा पूरे कार्यकाल में मीठा-मीठा गट और कड़वा-कड़वा थू ही करती दिखाई दी। लंबे समय के बाद जिले को मिले पुरूष आईएएस अधिकारी ने जिले वासियों की उम्मीदों को जरा ज्यादा ही जगा दिया। शुरूआती दौर में सबकुछ ठीक ही दिखाई दे रहा था लेकिन बाद में स्थिति यह हो गई कि 'नया मुल्ला जरा जोर से ही अजान देता है''। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिले की जनता की उम्मीदें भी धुमिल होती ही नजर आ रही है।

कलेक्टर के रूप में जिले में पदस्थ हुए योगेश तुकाराम भरसट की जब जिले में पदस्थापना हुई तो जिलेवासियों को कई उम्मीदें बंध गई कि, चलो जिले में महिलाओं के बाद अब कोई पुरूष अधिकारी जिले को मिला है ऐसे में जिले के विकास में भी तेजी आएगी। लेकिन जिलेवासियों की यह उम्मीद अब धीरे-धीरे धुमिल होती दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि, पिछले कुछ दिनों में जिले में कुछ मामले ऐसे आए है जिन्हे देखकर कलेक्टर की कार्यप्रणाली प्रभावी नहीं दिखाई दे रही है। बल्कि अ धि न स्त

अधिकारी, कलेक्टर को सबकुछ हरा-हरा ही दिखाने में लगे हुए है। जब से कलेक्टर जिले में आए है ब्लॉक वार जनसुनवाईयों का आयोजन हो रहा है। इन्ही जनसुनवाईयों में कई मामले ऐसे आ रहे है जो जिले की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे है। कभी जनसुनवाई में ऐसा मामला आ जाता है कि, मृत्यु के बाद लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, तो कभी इसी तरह की जनसुनवाई में मुर्दे आवेदन लेकर पहुंच रहे है। मंगलवार को थांदला ब्लॉक में हुई जनसुनवाई में एक ऐसा ही विकलांग दंपत्ती पहुंच गए जो जिला प्रशासन के रिकार्ड में मृत घोषित हो चुके है। यानि कलेक्टर के सामने मुर्दा दंपत्ति ने यह गुहार लगाई है कि, साहब हम जिंदा है। यह ऐसे मामले है जो जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त साबित करने के लिए काफी है। इस तरह के मामलों में कलेक्टर का रिएक्शन इतना प्रभावी नहीं दिखाई दिया जैसा कि होना था। ब्लॉक स्तर पर जनसुनवाई कोई नया आयोजन भी नहीं है। पिछली फोटो और खबर छपाउ कलेक्टर भी अपने फोटो छपवाने के लिए इस तरह के आयोजन कर चुकी है। मगर यह आयोजन महज दिखावटी ही साबित हुआ था। न तो ब्लॉक स्तर पर जन की सुनवाई हो सकी ना ही उनकी समस्या का समाधान। हुआ तो बस यह कि अगले दिन अखबारों में मेडम की फोटो और खबरें ऐसी छपी मानों बस जिले की समस्या समाप्त ही हुई समझो...? मगर कहते है ना हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर। अब जिले में आए नए कलेक्टर भी इसी तर्ज पर चल रहे है। अपने हर दौरे और निरीक्षण को प्रसारित और प्रचारित करने के भरसक प्रयास खुले तौर पर दिखाई दे रहे है।

पिछले दिनों राणापुर निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने राणापुर नगर के तालाबों और बस स्टेंड का निरीक्षण किया। तालाबों की सफाई के निर्देश दिए तो वहीं बस स्टेंड पर व्याप्त अव्यवस्थाओं को दुरूस्थ करने के भी निर्देश दिए यह अच्छी बात है। मगर कलेक्टर साहब को जिला मुख्यालय के गटर बन चुके तालाब अब तक दिखाई नहीं दे रहे है। इन्हे लेकर उन्होने अब तक ना तो नगरपालिका को निर्देशित किया है और ना ही किसी अन्य विभाग या अधिकारी को। निरीक्षण के दौरान वे आरटीओ बनते भी नजर आए। बसों में चढ़े यात्रियों से बात की और बसों में किराया सूची का निरीक्षण किया। जबकि यह काम उनका नहीं था वे चाहते तो उसी समय आरटीओ को निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दे सकते थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थी 'रील नहीं रियल लाइफ के नायक'। जबकि कलेक्टर के इस निरीक्षण के बाद भी स्थितियां ढाक के तीन पात ही है। अब भी जिला मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों से चलने वाली अधिकांश बसें या तो कंडम स्थिति में है या फिर अवैध परमीट पर दौड़ रही है। बसों में ना तो फायर सेफ्टि का कोई पता है ना ही फास्टेड बॉक्स। बावजूद इसके आरटीओ की इन बसों को खुली छूट कई सवाल खड़े कर रही है। इसी वजह से कलेक्टर का यह निरीक्षण भी सवालों के घेरे में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। क्या इस निरीक्षण का मकसद सिर्फ फोटो खिंचावना और छपवाना ही था या फिर असल में कलेक्टर को जिले में सफर कर रहे यात्रियों की चिंता थी...? अगर ऐसा है तो फिर कलेक्टर के इस निरीक्षण के दौरान जिले की आरटीओ कहां थी, क्या कलेक्टर ने उन्हे फोन पर निर्देशित किया...?

सवाल तो यह है कि, क्या बसें सिर्फ इन्ही कलेक्टर के कार्यकाल में चल रही है? इससे पहले भी तो बसें जिले में संचालित हो रही थी, मगर आरटीओ मेडम तभी जागती है जब प्रदेश में कोई हादसा बसों को लेकर सामने आता है वह भी महज कुछ ही समय के लिए। बाद में स्थिति ज्यौ की त्यो ही बनकर रह जाती है। आए दिन अखबारों में जिले में संचालित होने वाली बसों को लेकर खबरें छपती है लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। महज अखबारों को गोल-मोल वक्तव्य दे दिए जाते है।

कुल मिलाकर बात यह है कि, कलेक्टर के निरीक्षण करते फिरने से जिले का कुछ होने वाला नहीं है। कुछ करना है अगर तो फिर अपने अधिनस्तों की नकेल कसना होगी। अधिकारियों को मजबूर करना होगा कि वे अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाए। अगर ऐसा नही हुआ तो कलेक्टर को ही आरटीओ बनकर घूमते रहना पड़ेगा। और अगर यह कलेक्टर की सिर्फ फोटो खिंचाओ मुहिम है तो फिर जिले की आमजनता को बधाई कि जिले में एक बार फिर फोटो खिंचाउ और फोटो छपाउ प्रशासन और मुखिया मिला है। लेकिन जिला अभी भी उम्मीदो के सहारे टिका है, देखना है कलेक्टर श्री भरसट किस किनारे जा कर बैठते है।

जहां चाह वहां राह...

आधुनिक डेयरी फार्म के माध्यम से गांव की नारी शक्ति की मिसाल बन चुकी सरस्वती पाटीदार

माही की गूंज,बरवेट।

सरकार की योजना, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एवं इंदौर दुग्ध सहकारी संघ इंदौर मांगलिया के द्वारा हाल ही में दूध के दामों में की गई बढ़ोतरी ने छोटे पशुपालकों के लिए आय के नए रास्ते खोले हैं। झाबुआ जिला के कई पशुपालक इस बदलाव का लाभ उठाते हुए अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहे हैं। बरवेट गांव की नारी शक्ति की मिसाल बन चुकी सरस्वती पाटीदार इसी परिवर्तन का एक सफल उदाहरण हैं, जिन्होंने डेयरी व्यवसाय को अपनाकर गांव में प्रेरणादायक मिसाल कायम की है। पेटलावद विकासखंड के बरवेट गांव की सरस्वती पाटीदार पिछले एक दशक से डेयरी व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। शुरुआत उन्होंने मात्र दो दुधारू पशुओं से की थी। लेकिन समय-समय पर सरकार द्वारा दूध के दाम बढ़ाए जाने से उन्हें अपने डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाने का भरोसा मिला। आज उनके पास 20 गायें और 20 बछियां हैं और वे पूरी तरह संगठित और आधुनिक ढंग से अपनी डेयरी यूनिट का संचालन कर रही हैं।

प्रतिदिन 200 लीटर उत्पादन

वर्तमान में सरस्वती पाटीदार अपने फार्म से प्रतिदिन लगभग 200 लीटर दूध का उत्पादन कर रही हैं। उन्हें दूध की गुणवत्ता (फैट प्रतिशता) के आधार पर 38 से 42 रुपये प्रति लीटर का मूल्य मिल रहा है। परिवार के सदस्य उनके पति राजेश पाटीदार भी कार्यों में सहयोग देते हैं, साथ ही उन्होंने अपने फार्म पर एक व्यक्ति को रोजगार भी उपलब्ध करवाया है। सरस्वती पाटीदार बताती हैं कि, ÷दूध के अच्छे दाम मिलने से ही मैं अपने साथ एक व्यक्ति को रोजगार दे पा रही हूं। सरस्वती पाटीदार ने बताया कि उनके डेयरी फार्म से प्रतिमाह लगभग 2 लाख चालीस हजार रुपए की से होती है। जिसमे चारा, फीड, दवाइयां, बिजली और श्रम सहित सभी खर्चों को घटाने के बाद वे लगभग 80 हजार से एक लाख रु की बचत होती है जिससे 80 हजार रुपये का शुद्ध मुनाफा कमा लेते हैं। गांव की परिस्थितियों में यह आय एक मजबूत और स्थायी आर्थिक आधार का संकेत है।

मिला शासकीय योजनाओं का लाभ,आनंद जाकर प्रशिक्षण लिया

बरवेट की सरस्वती पाटीदार ने बताया कि मेने दुग्ध उत्पादक समिति बरवेट एवम आचार्य विद्यासागर योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में पेटलावद पशु चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर ने दो दुधारू उन्नत नस्ल की एच एफ गाय क्रय कर लाभ दिलाकर पशुपालन व्यवसाय शुरू किया। जिसमे दूध उत्पादन एवम बछिया पालन कर पशु धन और दूध को बढ़ाया। आज मेरे पास 20 दुधारू गाय है। जिनसे में रोजाना 200 लीटर दूध दुग्ध उत्पादन समिति को प्रदाय करती हु। इंदौर दुग्ध संघ द्वार 2017 में कृषक भ्रमण के लेकर गुजरात के आनंद में जाकर प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। जहा पर नई तकनीकी सीखकर मेने पहली बार गाय का एआई कर बछिया बड़ाकर दूध उत्पादन को बढ़ाया। मेने एक गाय से ही 20 दुधारू गायों को दूध उत्पादन को बढ़ाया। इसके साथ ही मेने गांव में अन्य महिला पशुपालकों को प्रेरित कर दूध व्यवसाय को बढ़ाया। आज 1400 लीटर दूध रोजाना संकलन किया जा रहा है और बरवेट दूध उत्पादन समिति ने प्रदाय किए जा रहे है। आज स्वयं के पास 40 पशुधन (गाय और बछिया) है।

आटोमेटिक सिस्टम लगा फार्म हाउस में

सरस्वती पाटीदार ने बताया कि पशुओं के रखरखाव में विशेष ध्यान दिया जाता है। उनके रहने के लिए आधुनिक फार्म हाउस बनाया है जिसने गर्मी में ठंडा रखने के लिए फोगर सिस्टम, पीने के पानी के लिए ओटोमेटिक बाउल सिस्टम, दूध दुहाने के लिए दूध मशीन, उनको आराम के लिए पशु मेट की व्यवस्था की गई है। समय समय पर डाक्टरों द्वारा गायों की जांच की जाती है। पशुपालन विभाग के उपसंचालक डा दिवाकर के निर्देशानुसार पशुओं (गायभैंस) का दूध बढ़ाने के लिए मक्के या चारे से बनी साइलेज (पसंहम) एक बेहद पौष्टिक और सुपाच्य आहार है। यह पशुओं को साल भर हरा चारा जैसा पोषण प्रदान करता है, जिससे दूध की मात्रा और गुणवत्ता में औसतन 10 से 15: तक की बढ़ोतरी हुई है।

गोबर गैस के साथ देसी खाद का भरपूर उत्पादन

सरस्वती पाटीदार ने बताया कि जब से मेने पशुपालन का व्यवसाय शुरू किया है तब से हमारे यहां गोबर गैस संयत्र लगा हुआ है। घर का खाना गोबर गैस पर बनता है। साथ ही साल भर में चालीस से पचास ट्रॉली देसी खाद निकलता है। जिसका उपयोग खेत में करते है। जिसकी बाजार कीमत डेढ़ लाख रुपए तक मिलती है।

सकल जैन समाज ने विहाररत संतों की सुरक्षा के लिए उठाई आवाज

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद में आज महावीर समिति के बैनर तले सकल जैन समाज ने एकजुट होकर विहाररत जैन साधु-संतों की सुरक्षा और हाल ही में रीवा में हुई आर्यिका माताजी की दुर्घटना की निष्पक्ष जांच को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। सकल जैन समाज के बैनर तले समाजजनों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार अनिल बघेल को सौंपा। समाजजनों ने स्पष्ट किया कि हाल ही में आर्यिका माताजी के साथ हुई दुखद घटना मात्र एक सड़क दुर्घटना नहीं है, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह गंभीर शंकाओं को जन्म देती है, जिसकी निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्चस्तरीय जांच अत्यंत आवश्यक है। जैन समाज ने अपनी मांगों को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि विहाररत संत पूरी तरह निहत्थे और अहिंसक होते हैं, जो समाज को शांति और संयम का संदेश देते हैं। उनके साथ लगातार बढ़ती दुर्घटनाएं और हमले पूरे समाज के लिए चिंता का विषय हैं।

उच्चस्तरीय जांच की मांग

समाज ने मांग की कि इस मामले की जांच एसआईटी या न्यायिक आयोग द्वारा कराई जाए और घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज व डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित कर दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित हो। ज्ञापन में समाज ने सुरक्षा के लिए ठोस नीति की वकालत की है।

महावीर समिति के अध्यक्ष संजय भंडारी , श्री संघ अध्यक्ष अशोक मेहता एवं तेरापंथ सभा अध्यक्ष नरेन्द्र पालरेचा ने मांग की है कि विहाररत संतों के लिए एक विशेष श्संत सुरक्षा प्रोटोकॉलश् लागू किया जाए, जिसके तहत विहार मार्गों पर प्रशासनिक समन्वय, पुलिस सहयोग, ट्रैफिक नियंत्रण और हाईवे व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरती जाए। सकल समाज ने राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाने की मांग भी की।

एसआईआर प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर दायर याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केवल इस आधार पर एसआईआर प्रक्रिया को अवैध नहीं कहा जा सकता कि यह सामान्य मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया से अलग है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि, संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग का यह कदम कानूनी रूप से सही है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना नहीं है। अदालत ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटने मात्र से किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं होती। नागरिकता का निर्धारण केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी थी कि, विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया सामान्य चुनावी नियमों से अलग है और इससे कई योग्य मतदाताओं के नाम सूची से हटने की आशंका बढ़ सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन आशंकाओं के आधार पर पूरी प्रक्रिया को रद्द करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि आयोग की शक्तियां असीमित नहीं हैं और उसे कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करना होगा।

85 वर्षीय गणपत लाल परमार आज भी रेडियो युग का ले रहे आनंद

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

आज के जमाने में लोगों के मनोरंजन के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक साधन आ चुके हैं लेकिन सारंगी में 85 वर्षीय गणपत लाल परमार रतलाम कलेक्टर ऑफिस में नकल विभाग में बाबू के पद पर अपनी सेवाएं दी। रिटायर्ड होने के बाद अपने ग्रह ग्राम सारंगी में निवास कर रहे हैं । बता दे कि आप दोनों पांव से विकलांग भी है और आज भी घर पर बैठकर लोगों के समस्या के आवेदन लिखकर समाधान कर रहे हैं। साथी अपने घर का गुजारा कर रहे हैं बता दे की उनकी पत्नी भी दोनों पांव से विकलांग है ।जब संवाददाता ने इनसे मुलाकात की तो यह रेडियो पर गाने सुन रहे थे उन्होंने बातचीत में बताया मैं टीवी नही देखता हूं मेरे पास यह पुराना रेडियो है इस पर में प्रादेशिक समाचार , राष्ट्रीय स्तर समाचार , गाने के साथ अन्य प्रोग्राम भी दिन भर सुनता रहता हूं मेरे टाइम पास का सिर्फ एक रेडियो ही मेरा साथी है मुझे रेडियो पर सारी जानकारी मिल जाती है। आज के युग में रेडियो का उपयोग कोई नहीं करता है मेरे हिसाब से सारंगी ग्राम में अकेला व्यक्ति हूं जो रेडियो मेरे पास है और मैं सारे प्रोग्राम सुनता हूं।

चलती ट्रेन से गिरी महिला गंभीर घायल

माही की गूंज ,बामनिया।

बुधवार को बामनिया और अमरगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच एक महिला के चलती ट्रेन से गिरने की घटना की जानकारी सामने आई है। जो महिला पश्चिम बंगाल की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर महिला को एम्बुलेंस की सहायता से पेटलावद सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए झाबुआ जिला चिकित्सालय रेफर किया गया।

बताया जा रहा है कि, महिला अपने पति के साथ गुजरात से अपने गांव पश्चिम बंगाल जा रहे थे। इसी दौरान बामनिया-अमरगढ़ रेलवे ट्रैक के बीच अचानक महिला चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। हादसा कैसे हुआ, इसका स्पष्ट कारण फिलहाल सामने नहीं आ पाया है। घटना के बाद आसपास के लोगों एवं रेलवे से जुड़े कर्मचारियों द्वारा तत्काल सहायता पहुंचाई गई।

क्वाड बैठक के बाद भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई मजबूती

नई दिल्ली, एजेंसी।

क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ द्विपक्षीय बैठक कर व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की पिछली मुलाकात के बाद विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के बीच सहयोग और तेज हुआ है। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में दोनों देश आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते को आगे बढ़ाते हुए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की दिशा में बातचीत कर रहे हैं।

विदेश मंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत हो रही है। उन्होंने संकेत दिया कि भारत ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति बढ़ाने का इच्छुक है, क्योंकि देश में परमाणु ऊर्जा के विस्तार की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दोनों देशों की टीमें महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता और सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने पर भी चर्चा कर रही हैं। बैठक में रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा भी प्रमुख मुद्दों में शामिल रहे। जयशंकर ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा अभ्यास तथा सैन्य आदान-प्रदान लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षित समुद्री व्यापार सुनिश्चित करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। क्वाड बैठक के संदर्भ में जयशंकर ने कहा कि, सदस्य देशों ने समुद्री निगरानी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली केबल्स, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और निर्बाध समुद्री व्यापार के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन बेहद जरूरी है।

दूसरे चरण में बरवेट हायर सैकेंडरी स्कूल सांदीपनि स्कूल के लिए मिली मंजूरी

माही की गूंज, बरवेट।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीएम राइज स्कूलों का नाम बदलकर सांदीपनि विद्यालय कर दिया गया है। सांदीपनि स्कूलों के दूसरे चरण के तहत राज्य में 205 नए सर्वसुविधायुक्त विद्यालय खोले जा रहे हैं। बरवेट में खुलने वाले नए सांदीपनि विद्यालय की सटीक स्थिति और निर्माण प्रगति के लिए जन जातीय कार्यालय भोपाल से एक आदेश जारी कर विद्यालय की सारी जानकारी के लिए स्कूल प्राचार्य से मांगी है। शासकीय हायर सैकेंडरी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य हिरजी निनामा ने बताया कि बरवेट हायर सैकेंडरी स्कूल का उन्नयन होकर संदीपनी स्कूल में परिवर्तित हो जाएगा। जिसके लिए संकुल केंद्र में दर्ज संस्था, कार्यरत कर्मचारी, स्वीकृत पद, प्राचार्य की फोन नंबर जानकारी मांगी गई है। ताकि माडल चयन प्रमाणिक दस्तावेज आज तारीख तक के उपलब्ध करवाए गए है। साथ ही आनलाइन जानकारी अपलोड की जाएगी।

छात्रों को मिलेगी सुविधाएं

सांदीपनि स्कूल खुलने से छात्रों को एक ही परिसर में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान संकाय के छात्रों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं खेल के मैदान और दूर दराज से आने जाने वाले छात्रों को बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सांदीपनि स्कूल की स्वीकृति के लिए दूसरे चरण में कैबिनेट द्वारा दूसरे चरण हायर सैकेंडरी स्कूल बरवेट को सांदीपनि स्कूल में परिवर्तित होने की स्वीकृति मिल चुकी है।

द्विशा शर्मा मौत मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ में

भोपाल।

राजधानी भोपाल में मॉडल और अभिनेत्री द्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने हाथ में ले ली है। सोमवार को सीबीआई ने भोपाल पुलिस से केस डायरी और अन्य दस्तावेज लेकर नए सिरे से प्राथमिकी दर्ज की। इस बीच कटारा हिल्स थाना पुलिस ने द्विशा के पति समर्थ सिंह से सात दिन की रिमांड के दौरान पूछताछ की, जिसमें कई अहम बातें सामने आई हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, समर्थ पूछताछ में वही बातें दोहरा रहा है, जिनका जिक्र उसकी मां गिरीबाला सिंह पहले भी कर चुकी हैं। समर्थ ने दावा किया कि शादी के शुरुआती दिनों में दोनों के संबंध सामान्य थे, लेकिन 17 अप्रैल को द्विशा के गर्भवती होने की जानकारी मिलने के बाद उसका व्यवहार बदल गया था। समर्थ के मुताबिक द्विशा अक्सर मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया का हवाला देते हुए कहती थी कि वह सामान्य घरेलू जीवन नहीं जी सकती। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे थे।

समर्थ ने पूछताछ में अप्रैल महीने की एक घटना का भी जिक्र किया। उसने बताया कि दोनों को साथ में बेंगलुरु जाना था, लेकिन अंतिम समय पर द्विशा ने मना कर दिया और कहा कि वह अपने भाई के पास अजमेर जा रही है। समर्थ के अनुसार वह अकेले बेंगलुरु चला गया, जबकि बाद में पता चला कि द्विशा अजमेर में केवल एक दिन रुकी और बिना बताए दिल्ली चली गई। इस बात को लेकर दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया था।

द्विशा की मौत वाली रात के बारे में समर्थ ने पुलिस को बताया कि उस दिन सब कुछ सामान्य था। दोनों ने साथ खाना खाया, सोसाइटी के पार्क में टहलने गए और बाद में घर लौटकर टीवी देखा। समर्थ के अनुसार वह सोने चला गया, जबकि ट्विशा नीचे जाकर अपने परिजनों से फोन पर बात करने लगी। देर रात उसकी मां गिरीबाला ने उसे जगाया और बताया कि ट्विशा की मां का फोन आया है, क्योंकि वह फोन नहीं उठा रही थी।

समर्थ के मुताबिक घर में तलाश करने पर द्विशा छत पर फंदे से लटकी मिली। उसने दावा किया कि उसने और उसकी मां ने मिलकर द्विशा को नीचे उतारा, सीपीआर दिया और तुरंत एम्स भोपाल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद फरार रहने को लेकर समर्थ ने पुलिस को बताया कि, वह एक सप्ताह से अधिक समय तक जबलपुर में छिपा रहा। गिरफ्तारी के डर से उसने मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी बंद कर दिया था ताकि पुलिस उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि फरारी के दौरान समर्थ की मदद किसने की।

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को सुनवाई की। अदालत ने कहा कि एक महिला की असामयिक मौत गंभीर विषय है और इसकी सच्चाई सामने आना जरूरी है।

रेलवे स्टेशन के समीप मिला शव, पीएम रिपोर्ट के बाद हत्या का मामला हुआ दर्ज

जांच में जुटी पुलिस, रेलवे ओर सीटी पुलिस में सीमा क्षेत्र को लेकर रहता है असमंजस

माही की गूंज, बामनिया।

सोमवार सुबह बामनिया-खवासा मार्ग पर रेलवे प्लेटफार्म खत्म होने के बाद वॉलबाउंड्री के निकट सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला रेलवे पुलिस के पास पहुंचा लेकिन रेलवे पुलिस ने शव का बामनिया चौकी क्षेत्र में होना बता के बामनिया पुलिस को सूचना कर अपने कार्य की इति श्री कर ली। लगभग दो घंटे शव पड़ा रहा। उसके बाद समीपस्थ ग्राम पंचायत मूलथानिया के ग्राम सातेर की एक महिला मौके पर पहुंची और उसे अपना पति बताते हुए उसकी पहचान की।

दो घंटे बाद पहुंची पुलिस

रेलवे ओर सीटी पुलिस के बीच सीमा क्षेत्र को लेकर काफी देर तक खींच-तान चलती रही जिसके बाद आखिर बामनिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पीएम के लिए पहुंचाया। शुरुवाती जांच में मामला कुछ साफ नहीं था कि युवक की मौत कैसे हुई। पुलिस ने मृग कायम कर जांच शुरू की तो मृतक की पहचान सुखराम पिता नहार सिंह निनामा निवासी ग्राम पीपलीपाड़ा थाना मेघनगर के रूप में हुई।

चौकी प्रभारी मालिवाड ने बताया कि, पीएम रिपोर्ट आने के बाद मामले में बीएनएस की धारा 103 व अन्य धाराओं में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ट्रेन में करता था फेरी, स्टेशन ही था ठिकाना

मिली जानकारी के अनुसार मृतक, रेलवे स्टेशन पर सोता था और अपनी पत्नी के साथ रतलाम मजदूरी करने ओर रतलाम-मेघनगर चलने वाली ट्रेनों में फेरी लगा कर सामान बेचने का काम भी करता था। युवक ओर उसकी पत्नी रविवार को स्टेशन पर देखे गए लेकिन बाद में युवक की पत्नी उसके मायके सातेर चली गई ओर मृतक रात में अकेला स्टेशन पर था और सुबह उसका शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस मामले में अलग-अलग पहलुओं से मामले को जोड़ कर जांच कर रही है। मृतक ओर उसकी पत्नी के मोबाइल नहीं होने से मामला अंधे कत्ल की ओर चला गया है। जहां पुलिस को मामला सुलझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। बीते एक माह में पेटलावद थाना क्षेत्र में हत्या की ये तीसरी वारदात है जिसमें से कोदली ओर करवड़ चौकी क्षेत्र में हुए हत्या के मामले पुलिस ने सुलझा लिए है ओर बामनिया का मामला पुलिस के जांच में है।

8 वे पर स्कूटी दुर्घटना ग्रस्त, एक की मौत, एक जख्मी

माही की गूंज, खवासा।

मौत कब, किसको और कहां अपने आगोश में ले-ले कहा नहीं जा सकता। इसीलिये कहते हैं जब तक जीये तब तक हम सबसे हंस-बोलकर जीये। और इस वाक्य को सही साबित भी किया रिटायर्ड शिक्षक कैलाश शर्मा व उनके ही साथी शिक्षक रहे सुभाष शर्मा ने। जो अपनों से मिलने आए और हंसी-खुशी सभी से मिले और वापसी अपने घर रतलाम जाते समय स्कूटी दुर्घटना ग्रस्त हो गई और रिटायर्ड शिक्षक कैलाश शर्मा की मौत हो गई।

बता दे कि, कैलाश शर्मा जो की खवासा बालक के साथ कुकड़ीपाड़ा व भामल संकुल के लेखापाल के पद पर करीब 27 साल यहां नौकरी कर 6 माह पूर्व रिटायर्ड हुए थे। वहीं उनके साथी शिक्षक बालक हायर सैकेंडरी स्कूल में पदस्थ रहे और करीब 3 वर्ष पूर्व रिटायर्ड हुए थे। वहीं कैलाश शर्मा रतलाम 80 फीट रोड पर तो सुभाष शर्मा साक्षी पेट्रोल पंप के पीछे रतलाम में निवासरत थे।

बताया जा रहा है कि, दोनों शर्मा बन्धु की शिक्षकीय सेवा के दौरान अच्छी दोस्ती थी। वहीं 25 मई सोमवार को सुभाष जी शर्मा ने कैलाश जी शर्मा से चर्चा कर प्रोग्राम बनाया कि, 15 दिन से अधिक खवासा वालों से मिले हो गया है आज खवासा-थांदला जाकर सभी से मिल आते हैं। सुभाष सर के कहने पर कैलाश सर ने भी हां कर दी और दोनों मित्र अपने मित्रों से मिलने रतलाम से स्कूटी से निकले और खवासा आए। खवासा में सीएम राईस स्कूल भी गए यहां के प्राचार्य मोदी सर व अन्य शिक्षकों से भी मिले। कुछ गांव के व्यक्ति से भी मिले और सभी से हंस बोलकर थांदला रवाना हुए। थांदला भी अपने परिचितो व मित्रों से मिलकर टिमरवानी से रतलाम के लिए 8 वे पर चढ़े।

कैलाश जी शर्मा

दोनों शिक्षक अपनी पुरानी यादों को ताजा कर वार्तालाप करते हुए स्कूटी से रतलाम अपने घर जा रहे थे कि, ऊपर वाले की लिखी के चलते स्कूटी अनबैलेंस होकर सड़क के साईड में बने लोहे के डिवाइडर से जोरदार जा भीड़ी जिससे सुभाष जी शर्मा व केलाश जी शर्मा दोनों को सीने में चोटें आई। और कैलाश जी शर्मा की रतलाम अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तथा मंगलवार को कैलाश जी शर्मा का रतलाम मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार हुआ।

वही बताया जा रहा है कि, सुभाष जी शर्मा सर भी सीने में चोट लगने से गंभीर अवस्था में है।

जानकारी रखने वाले ने बताया कि, बुधवार समाचार लिखे जाने तक सुभाष सर का उपचार रतलाम के गीता देवी हॉस्पिटल में हो रहा है। तथा जख्मी अवस्था को देखते हुए परिजन बड़ौदा उपचार हेतु ले जाने का विचार-विमर्श किया जा रहा है।

हम आशा करते हैं कि, सुभाष सर जल्द उपचार के साथ स्वस्थ हो जाए और असमय काल के ग्रास बने कैलाश जी शर्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।

युवक की हत्या का खुलासा, पीएम रिपोर्ट में सामने आई गंभीर चोटें

माही की गूंज, खंडवा।

खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के टिगरिया गांव में 16 मई को मिले युवक के शव मामले में हत्या की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि 40 वर्षीय मृतक के कंधे में फैक्चर था तथा सिर के पीछे कनपटी के पास गंभीर अंदरूनी चोट पाई गई। शव मुंह के बल पड़ा मिला था। घटना के बाद से पुलिस को अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे मामला अंधे कत्ल बन गया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी के परिचित युवक को हिरासत में लेकर करीब तीन दिन तक पूछताछ की। हालांकि पूछताछ में उसने घटना में शामिल होने से इनकार किया। पुलिस ने अन्य लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन अभी तक कोई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ नहीं लगी है।

हत्या की आशंका सामने आने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विशेषज्ञ चिकित्सकों से दो बार राय ली। चिकित्सकों ने किसी दुर्घटना की संभावना से इनकार करते हुए इसे हत्या का मामला बताया। मृतक के एचआईवी संक्रमित होने के कारण चिकित्सकों ने पूरी सावधानी बरतते हुए पीपीई किट पहनकर पोस्टमार्टम किया।

मूल रूप से हरदा निवासी मृतक करीब 8 से 9 महीने पहले एचआईवी जांच में संक्रमित पाया गया था। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच कराई गई थी, जिनकी रिपोर्ट सामान्य आई थी। जानकारी के अनुसार युवक लंबे समय से परेशान चल रहा था और शराब पीने का आदी हो गया था। वह महीने में कभी-कभार ही अपने परिवार से मिलने आता था।

वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी

माही की गूंज, उज्जैन। जिले में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थबाजी हुई है। पत्थरबाजी की घटना में चार-पांच कोचों के शीशे टूट गए हैं। घटना के समय यात्री भयभीत हो गए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है।

दरअसल, हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पर सोमवार रात पथराव की सनसनीखेज घटना सामने आई थी। उज्जैन स्टेशन के पास ट्रेन पर हरिफाटक ब्रिज के नीचे अज्ञात बदमाशों ने अचानक पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में ट्रेन के 4 से 5 कोचों के कांच टूट गए और अंदर बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन हरिफाटक पुल के नीचे से गुजर रही थी, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने लगातार पत्थर फेंके। तेज आवाज के साथ कांच टूटते ही यात्री सहम गए। कई लोग सीट छोड़कर नीचे झुक गए, जबकि महिलाओं और बच्चों में चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे स्टाफ और सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे। एहतियात के तौर पर ट्रेन को कुछ देर रोका गया और सभी कोचों की जांच की गई। राहत की बात यह रही कि किसी यात्री को चोट नहीं आई।अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मगर कुछ देर तक यात्री सहमे रहे हैं।

आरपीएफ थाना प्रभारी नरेंद्र यादव के अनुसार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने दिए निराकरण के निर्देश

माही की गूंज, थांदला।

कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट द्वारा मंगलवार को थांदला में विकासखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में नागरिकों ने विभिन्न समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए, जिन पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों को त्वरित एवं आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में ग्राम परवाड़ा के धोबड़ी फलिया के ग्रामीणों ने धोबड़ी फलिया से लिमड़ी फलिया स्कूल तक लगभग एक किलोमीटर मार्ग पर पक्की सड़क नहीं होने की समस्या बताई। ग्रामीणों ने बताया कि, मार्ग अत्यंत खराब स्थिति में है, जिससे आवागमन बाधित होता है तथा बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के समय सड़क पर कीचड़ एवं पानी भर जाने से मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है। इस पर कलेक्टर ने जांच कर आवश्यक कार्यवाई करने तथा आवेदकों को सूचित करने के निर्देश दिए।

गांधी चौक थांदला निवासी रणछोडलाल पिता रामचंद्र चिकलीगर एवं श्रीमती शारदा पति रणछोडलाल चिकलीगर ने वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया।

ग्राम भेरूपाड़ा निवासी कलसिंह माल ने आवेदन देकर बताया कि, ग्राम की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 650 पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे आम लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। साथ ही उक्त भूमि पर स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य भी बाधित किया जा रहा है। उन्होंने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण प्रारंभ कराने की मांग की।

ग्राम रुंडीपाड़ा निवासी कालू भावचंद डामोर ने खाद्यान्न पर्ची चालू करवाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक दस्तावेज ग्राम पंचायत सचिव को जमा कराने के बावजूद खाद्यान्न पर्ची प्रारंभ नहीं की गई है, जिससे परिवार को राशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

ग्राम तलावली के ग्रामीणों ने खाली फलिया में गंभीर पेयजल संकट की समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि, दो फलियों के लोगों को लगभग दो किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है तथा गांव के हैंडपंप सूख चुके हैं अथवा खराब पड़े हैं। ग्रामीणों ने सुरमल पिता सकरिया वसुनिया के घर के सामने मुख्य मार्ग पर नए हैंडपंप खनन की मांग की।

ग्राम सेमलिया मुणिया फलिया के ग्रामीणों ने गांव में पेयजल, सड़क एवं बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी की समस्या बताई। ग्रामीणों ने कहा कि बारिश के मौसम में मार्ग नहीं होने से आवागमन में अत्यधिक परेशानी होती है तथा गांव में पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थांदला अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों (डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं मल्टी स्किल ग्रुप-डी) ने आवेदन देकर बताया कि, उन्हें पिछले चार से पांच माह से मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे आर्थिक एवं पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

जनसुनवाई के दौरान लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत कुमारी सोनाक्षी चौहान को आश्वासन पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के दो हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए तथा तीन हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए।

थांदला में आयोजित जनसुनवाई में कुल 119 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं जिला मुख्यालय पर अपर कलेक्टर श्री सी.एस. सोलंकी एवं संयुक्त कलेक्टर विजय कुमार मंडलोई द्वारा आयोजित जनसुनवाई में कुल 90 आवेदन प्राप्त हुए।

पलायन से परिवार का पालन और प्रशासन प्रभावहीन

जनजाति क्षेत्र में पलायन के सामने घुटने पर टीकी सरकारी योजनाएं

माही की गूंज, झाबुआ। रिंकेश बैरागी

जनजाति क्षेत्र के लिए पलायन एक अभिशाप सा है। पलायन पर जाने वाले मजबूरी में अपना घर त्यागकर मजदूरी के लिए निकलते हैं, उनके पास अन्य राज्यों में जा कर काम करके परिवार का जीवन व्यापन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। ग्रामीण कुछ महिनो का राशन, और सामग्री लेकर कामकाज की तलाश में निकल कर अपना घर, गावं, जिला और राज्य छोड़कर अन्य प्रदेश में बरसों से जा रहें हैं। अपनी सुविधा और जीवन यापन के लिए उनके द्वारा लिया गया कर्जा जिले में रहकर दिन दुनी, रात चौगुनी रुप से बढ़ता है। कर्जे के उस चक्र के चक्कर को समाप्त करने के लिए जनजाति समाज पलायन के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं।

त्योहार और विवाह की समाप्ती के बाद जिले में शाम के समय लंबी रुट वाली बसो के रास्ते पर स्थान-स्थान पर बोरियां-बिस्तर के साथ ग्रामीण रात भर बैठे हुए मिलते हैं। जीवन की व्यवस्था के लिए अधिकतर गुजरात, राजस्थान, और महाराष्ट्र राज्य में पलायन के लिए जाते हैं, क्योंकि इनको अपने ही अंचल में कार्य की इतनी सुविधा या रोजगार नहीं मिलता कि, ये लोग यहां रहकर गुजर-बसर कर सके। प्रशासन की योजनाओं पर क्रियान्वन का प्रतिशत इस दृश्य पर फिका सा दिखाई पड़ता है। वहीं शासन के दावे और वादे शक्तिहीन और बेबुनियादी से प्रतित हो कर घुटनों पर टीके हुए दिखाई देते हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो वो जनजाति समाज के पलायन के इस नासुर घाव को कभी भर नहीं पाई। जनजाति क्षेत्र के नेता अपने ही समुदाय के लोगों को इस स्तर पर बेवकूफ बनाते आते रहें और अपनी झोलिया भरते रहे, सुविधाओं और योजनाओं की पुर्ति के लिए अपने अधिनस्थ कार्यकर्ताओं को लाभांवित कर इतिश्री करते आ रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरुप आज भी ग्रामीण निर्धनता के वश में पलायन के चक्र में चलते-चलते पेरो में छाले कर लेते हैं और उसी चक्र को फिर उसका वंशज पलायन के चक्र में फंस कर चलने को मजबूर हो जाता है। लेकिन निर्मम नेता निर्लज्ज होकर इस युक्ति को देखता है परंतु कभी इस समस्या के समाधान पर सुविचार नहीं रखता।

नेता, विधायक, सांसद, विधानसभा या संसद में आवाज ऊंची कर जनजाति क्षेत्र की निर्धनता, बेरोजगारी, और अन्य असुविधाओ से अवगत करवाकर सरकार से योजनाओं का भंडार खुलवाता है। मगर वो सारी सुविधा और योजना का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंचता, बल्कि नेता अपने विशेष चाटुकारों को देकर सारा खजाना लूट लेते हैं। तभी तो हर त्योहार के पश्चात ग्रामीणों की भीड़ अन्य राज्य में काम पर जाने के लिए बहुत से स्थानों पर देखने को मिल जाएगी। प्रश्न की प्राथमिकता यह है कि, जनजाति क्षेत्र में सरकारी योजनाओं पर ठीक से कार्य किया जाए तो ग्रामीण पलायन पर जाएगा ही क्यों...?

पलायन पर जाने वाले ग्रामीणों ने बताया कि, घर पर दो बुजुर्ग को छोड़कर बाकी सभी काम पर जाते हैं। इसी कारण वश उनके बच्चें शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और इसी कारण ही बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ता हैं।

पलायन की मजबूरी है क्योंकि खेत है किंतु पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं, जहां है वहां इतना कम कि, फसल को पकाया नहीं जा सकता। जल की व्यवस्था करने के लिए शासन ने बहुत सी योजनाओ को लागु किया, जिसमें कुएं, नहर, बोरी बांध, तालाब निर्माण, हेण्डपंप खनन, ट्युबेल किया जाता है। लेकिन लचर प्रशासन की व्यवस्था पर भ्रष्टाचार का किड़ा ग्रामीणों को मिलने वाले पर्याप्त लाभ को चाट जाता है, और ग्रामीणों के अपने ही समुदाय के नेता, प्रतिनिधी होने पर भी स्वयं को असहाय महसुस करते हैं।

दूसरा मुख्य कारण अंचल में कार्य का अभाव जिससे ग्रामीण परिवार को पालने की प्रक्रिया में पलायन के पथ पर परिवार के साथ परिजनों से दूर चला जाता है। इस समस्या के निवारण के लिए सरकार ने जिस योजना का क्रियांवन कर अपनी पीठ थपथपाई वो भी प्रशासन के लालची स्वभाव में आकर बंदरबांट की भेंट चढ़ गई। इस योजना में ग्रामीणों को 100 दिन का रोजगार पंचायत द्वारा दिया जाना होता था। लेकिन वहां भी भ्रष्टचार का दीमक पहले से ही मौजुद होकर निर्धन ग्रामीण के लाभ को खा जाता है। पंचायत स्तर पर बहुत सी बार मजदूरो के बजाय मशीनों से कार्य करवाया जाता और वे मशीने या तो नेता के प्रतिनिधी की होती है या फिर स्वयं सरपंच या नेता की होती है। जहां कहीं मजदुरो से कार्य करवाया भी जाता है वहां भी 10 प्रतिशत लिस्ट में नाम ऐसे लिखे जाते हैं जो उस स्थल पर कार्य नहीं कर रहें होते, और 10 प्रतिशत वो होते हैं जो आधे दिन काम कर पूरा मेहताना लेते हैं। इन 20 प्रतिशत मजदूरो की मजदूरी दर्शाई जाती है और उस पर भ्रष्टचार का तिलक लगता है।

तीसरा मुख्य कारण है, ग्रामीणों पर कर्ज जिसके चक्रव्युह में जनजाति समुदाय का व्यक्ति न चाहते हुए भी फंस जाता है, और फिर उस कर्ज को उतारने के लिए ब्याज के काटेदार पहिए में गोल-गोल घुम कर अपना सबकुछ गवां देता है। कभी-कभी तो कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और उसे समाप्त करने के लिए या तो उसे पुरखो की भूमि बेचना पड़ती है या फिर पलायन के रास्ते पर प्रगाढ़ होना पड़ता है। शासन ने इस समस्या के निवारण के लिए बहुत से वादे किए, सुदखोरो के विरोध में नियम कानुन को लाया गया, सभी प्रकार की बैंक से लोन की सरल योजनाओं को बनाया, खेत पर फसल के लिए भी लोन सुविधा दी गई। परंतु फिर से लचर व्यवस्था ने प्रत्येक निर्धन के लाभ पर पानी फेरा। बैंक लोन भी अच्छा खासा कमिशन या रिश्वत देकर दिया जाता है और यदि सबकुछ ठीक रहता है तो लोन मिलने का समय इतना अधिक हो जाता है कि, ग्रामीण ब्याज के भार में दब जाता है। कर्ज कुप्रथाओ, दहेज-दापा, के कारण बहुत अधिक हो जाता है, जिसे ग्रामीण चाह कर भी नहीं बच पाता।

रिंकेश बैरागी

बहरहाल, पलायन के पथ पर अग्रसर परिवार पेट पालने की परिक्रमा में भावी पीढ़ी के भविष्य को पथभ्रष्ट कर देते हैं। उनके साथ जाने वाले बच्चें शिक्षा से वंचित रहते हैं और जागरुकता के अलख से दूर वो भी आने वाले समय में पलायन के अंधकार में जाने को मजबूर होते है। जबकि जिले में अनेक योजना में सेकड़ो तालाब स्वीकृत है, कई नदियां अब बहती नहीं है लेकिन शासन-प्रशासन नाकाम होकर नजारों को निहार रहा है।

पलायन के इस दृश्य को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि, शासन के सारे दावे और प्रशासन की मेहनत एक प्रकार का दिखावा है, बेइमानी है और जनजाति समाज के साथ बहुत बड़ा धोका है।

संपादकीय

रुपये की गिरावट

यूं देश के आयात-निर्यात असंतुलन के चलते पिछले दो दशकों से रुपये के मूल्य में लगातार गिरावट देखी गई है, लेकिन हाल के कुछ महीनों में इस गिरावट में तेजी आई है। खासकर ईरान-अमेरिकी युद्ध शुरू होने के बाद इसमें छह फीसदी की चिंताजनक गिरावट आई है। जो हमारी आयात पर अत्यधिक निर्भरता को ही दर्शाता है। यद्यपि दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऐसे मुद्रा संकट कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया गिरावट हमारी चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल, यह गिरावट भू-राजनीतिक अस्थिरता, कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित तेजी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता से मुद्रास्फीति और धीमी वैश्विक आर्थिक वृद्धि के बीच हो रही है। इन दबावों ने मिलकर एक ऐसा संवेदनशील वातावरण बनाया है, जिसमें रुपये की कमजोरी व्यापक आर्थिक व्यवधानों को जन्म दे रही है। वैसे तो बढ़ता आयात असंतुलन ही रुपये की गिरावट के मूल में है। सबसे बड़ा संकट तो कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता का है, जो करीब 88 फीसदी है। इसके अलावा खाद्य तेल, उर्वरक आदि आवश्यक वस्तुओं का आयात लगातार बढ़ा है। वहीं रुपये के डॉलर के मुकाबले लगातार गिरने से ये वस्तुएं महंगी हो गई हैं। खासकर ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर परिवहन, मालभाड़ा वृद्धि, भोजन और घरेलू खर्चों पर पड़ा है। इसके चलते रुपये के अवमूल्यन से कंपनियां तथा देश के नीति-निर्माता भी खासे चिंतित हैं। विदेशी मुद्रा में ऋण लेने वाली भारतीय कंपनियों पर ऋण चुकाने का अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है।

दरअसल, इन सभी कारणों से बढ़ते व्यापार घाटे का चालू खाते के घाटे पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। जिसके चलते शेयर बाजार में लगातार गिरावट का ट्रेंड देखा जा रहा है। वास्तव में विदेशी निवेशक अनिश्चितता के वातावरण में सुरक्षित अमेरिकी कंपनियों में निवेश बढ़ा रहे हैं। फलतरू अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश में लगातार निकासी का रुझान देखा जा रहा है। जिसने हमारी आर्थिक चिंताओं को और बढ़ाया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस जारी अस्थिरता को कम करने के लिये विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से हस्तक्षेप किया है, लेकिन ऐसे उपाय महज गिरावट की गति को कम करने के अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने तर्क दिया है कि रुपये का स्वाभाविक रूप से अवमूल्यन करने से समय के साथ व्यापार असंतुलन को दुरुस्त करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने केंद्रीय बैंक से आग्रह किया है कि वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान के कारण होने वाले मुद्रा के उतार-चढ़ाव से निपटने के लिये विशिष्ट विनिमय दर लक्ष्यों मसलन सौ रुपये प्रति डॉलर से आगे बढ़कर विचार करना चाहिए। हालांकि, अनियंत्रित अवमूल्यन से गंभीर जोखिम भी पैदा हो सकते हैं। देश के नीति-निर्माताओं को बाजार समायोजन की अनुमति देने और अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के बीच सावधानी से संतुलन बनाने की जरूरत होगी। निश्चित रूप से सरकार की ओर से मुद्रास्फीति का कुशल प्रबंधन और अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा बनाये रखना, देश की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो सकता है।

शातिर सत्ताधीशों की सियासत का शिकार गोवंश

भाजपा शासित राजस्थान में जैसलमेर में घटी एक अत्यंत संवेदनशील घटना ने देश के गौ भक्त समाज को झकझोर कर रख दिया। यहां के डंपिंग यार्ड में 500 से अधिक गायों के सड़े-गले शव और हड्डियां खुले में बिखरे हुए मिले पाये गये। इस जगह का दृश्य इतना भयावह व भीषण दुर्गंध पूर्ण था कि स्थानीय लोग और गौ-प्रेमी स्वभाविक रूप से इसे देखकर क्रोधित व विचलित हो गए। बताया जाता है कि इनमें से कई गायों की मौत जहरीला कचरा या पॉलीथिन खाने से हुई। जबकि इनमें बड़ी संख्या में ऐसी गायों के शव भी थे जिन्हें मृत पशुओं का निस्तारण करने वाले ठेकेदार ने इसी डंपिंग यार्ड में लाकर फेंक दिया था। भाजपा शासित राजस्थान में घटी इस दर्दनाक व शर्मनाक घटना ने सरकार व निजी गौ रक्ष संगठनों के गौ-रक्षा के दावों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि यह केवल किसी की लापरवाही मात्र का नहीं बल्कि मानवता और हिन्दू आस्था दोनों के ही अपमान से जुड़ा मामला है।

गौरतलब है कि पिछले एक दशक से देश में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों को गौरक्षा के नाम पर मारा जा चुका है। मुहम्मद अखलाक और पहलू खान जैसे अनेक लोगों की हत्या की खबरें देश विदेश के मीडिया में प्रसारित होकर देश की बदनामी का कारण भी बन चुकी है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016-17 में इन्हीं कथित गौरक्षकों के संदर्भ में यह कह भी चुके हैं कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले 70-80 प्रतिशत लोग फर्जी हैं, जो रात में गैर-कानूनी काम करते हैं और दिन में गोरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मोदी ने कहा था कि उन्हें उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जो गोरक्षा के नाम पर अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए हैं। उन्होंने राज्य सरकारों से ऐसे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करने और उनका डोजियर तैयार करने को भी कहा था। उस समय मोदी ने गोरक्षा के नाम पर

हो रही हत्याओं की कड़ी निंदा भी की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि गौ भक्ति के नाम पर लोगों की हत्या स्वीकार्य नहीं है।किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। उन्होंने असली गोरक्षकों को सलाह दी थी कि उन्हें गायों को प्लास्टिक खाने से बचाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि कटने से ज्यादा गायें प्लास्टिक और कचरा खाने से मरती हैं।

गाय को लेकर बने देश के इसी तनावपूर्ण वातावरण में देश के मुस्लिम समाज ने उच्च स्तर पर कहीं फतवों से तो कहीं दिशा निर्देश जारी कर भारत के मुसलमानों को यह हिदायत जारी की है कि वे गाय की हत्या व गोमांस भक्षण यदि कहीं किया जा रहा है तो उससे पूरी तरह बाज आयें। यहाँ तक कि देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर अनेक प्रमुख मुस्लिम उलेमाओं और संगठनों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की वकालत की है। इनके अनुसार ऐसा करने से देश में नफरत और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी, और बहुसंख्यक समाज की आस्था का सम्मान होगा। कई इस्लामी विद्वानों और मौलानाओं का तो स्पष्ट मत है कि इस्लाम में गौ मांस खाने को सख्ती से मना किया गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों का हवाला देते हुए मौलानाओं द्वारा यह बताया गया है कि गाय के मांस में बीमारी है और उसके दूध में शिफा अर्थात राहत है। अनेक मुस्लिम संगठनों ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है, ताकि गाय को लेकर होने वाली सांप्रदायिक राजनीति पर पूर्ण विराम लग सके।

परन्तु हिंदूवादी संगठनों द्वारा गौ हत्या को लेकर केवल मुसलमानों पर निशाना साधने वालों को इसी सिक्के के दूसरे पहलू को समझना भी जरूरी है। इस सन्दर्भ में पिछले दिनों हुए असम चुनावों के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का वह बयान काबिल -ए -गौर है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार लोगों के घर के अंदर गोमांस खाने अर्थात निजी खान-पान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। उन्हें इसे खाने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसे सार्वजनिक तौर पर खाने के बजाय अपने घरों के अंदर खाना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक रूप से या धार्मिक स्थलों के आसपास इसका सेवन कानूनन और सामाजिक भावनाओं के खिलाफ है। सवाल यह है कि जब गोवध होगा तभी तो गोमांस घरों में भी खाया जा सकेगा ? दूसरे यह कि केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों व जातियों के लोगों द्वारा भी बड़ी संख्या में गौमांस भक्षण किया जाता है तभी वोट बैंक के मद्देनजर यह बयान मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया। इसी तरह अप्रैल 2017 में केरल के मल्लापुरम लोकसभा उपचुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार एन. श्रीप्रकाश ने मतदाताओं से वादा किया था कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाले बीफ की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे और साफ-सुथरे बूचड़खाने खुलवाएंगे। जबकि अभी पिछले दिनों बंगाल में सत्ता में आई भाजपा सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानूनन केवल उसी गोवंश (गाय) का वध नहीं किया जा सकता जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो। इस कुतर्क के अनुसार क्या 14 वर्ष से ऊपर की गाय गौ माता की श्रेणी से बाहर हो जाती है?

भारत सरकार में संसदीय कार्य व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का 2015 में दिया गया वह बयान पूरे देश को याद ही होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ और गोमांस खाता हूँ। क्या कोई मुझे ऐसा करने से रोक सकता है? उनका तर्क था कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत से लोग बीफ खाते हैं और किसी के खान-पान की आदतों या जीवनशैली को उन पर थोपा नहीं जा सकता। साथ ही उसी समय उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि भारत विविधताओं का देश है। जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां उनकी आस्था और भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। गोरक्षा पर राजनीति करने वाली सरकार किरेन रिजिजू जैसे गौ मांस भक्षक को मंत्री बनाकर किस आधार पर गोरक्षा की बात कर सकती है ? उधर यही भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बांड के जरिए भारत की सबसे बड़ी बीफ निर्यातक कंपनियों से लगभग प्रत्येक चुनावों में करोड़ों का चंदा वसूलती है। इसी सत्ता संरक्षण की वजह से 2014 के बाद यानी भाजपा के शासनकाल में भारत का कुल बीफ निर्यात काफी बढ़ चुका है। परन्तु स्वयंभू गोरक्षकों को गोहत्या को बढ़ावा देने व इसके पक्ष में तर्क देने वालों से कोई शिकायत नहीं है बल्कि आश्चर्य है कि इनकी सारी दुश्मनी व शिकायत केवल मुसलमानों से ही है ? समझा जा सकता है कि गोवंश की सुरक्षा किसी धर्म जाति से जुड़ा विषय नहीं बल्कि वास्तव में गोवंश शातिर सत्ताधीशों की सियासत का शिकार है।

निर्मल रानी

बेटी पढ़ा तो लें मगर बचाएं कैसे ?

पिछले दिनों से त्विशा शर्मा का केस चर्चा में है। एक दिन में ही अखबारों के कुछ शीर्षक देखिएकृसंदिग्ध हालत में महिला की मौत। त्विशा-दीपिका की मौत ने दिखाया आईना। विनोद नगर में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत आदि-आदि। ऐसी खबरें रोज आती हैं। एक महिला कमांडो तक की पीट-पीटकर हत्या की जा चुकी है। एनसीआरबी के 2024 के आंकड़ों की मानें, तो दहेज हत्या के मामलों में दिल्ली सबसे आगे फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक का नम्बर है।

पिछले कुछ सालों से तो लगता था कि अब देश में बहुत बदलाव हो गया है। शादियां समानता के आधार पर हो रही हैं। इसका बड़ा कारण लगता कि चूंकि लड़कियां पढ़-लिख गई हैं, तो वे स्वयं भी ऐसे युवकों से विवाह करने से मना कर देती हैं, जिनके परिवार उन्हें अपने अनुकूल नहीं लगते। ऐसे बहुत से विवाह होते भी देखे हैं। आसपास ऐसे कई परिवार भी रहते हैं, जहां लड़कियां विवाह के बाद संयुक्त परिवारों में रहती हैं, कोई लड़ाई-झगड़ा भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अब सोचती हूं कि जो दिखता है, वही सच नहीं होता। उसके पीछे भी बहुत कुछ छिपा रहता है।

अक्सर हम मध्यवर्ग के लोग हर बात अशिक्षा से जोड़ देते हैं कि फलां ने ऐसा इसलिए किया होगा कि परिवार शिक्षित नहीं था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन त्विशा के मामले पर नजर डालें, तो उसके ससुराल में सब पढ़े-लिखे थे। सास रिटायर्ड जज, पति आपराधिक मामलों का वकील। फिर भी जब इस लड़की ने आत्महत्या कर ली, तो इसकी पहली सूचना उसके परिवार वालों को नहीं दी गई, बल्कि सास अपने जान-पहचान वालों से बातचीत करती रही। छियालीस फोन किए गए। एम्बुलेंस और पुलिस को फोन नहीं किया गया। यही नहीं सास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए, वे, वे ही थे जिन्हें आम तौर पर लड़कियों के चरित्र हनन के लिए लगाया जाता है। जैसे कि वह ड्रग एडिक्ट थी। एक दिन के लिए घर से बाहर चली गई थी। उसने गर्भपात करा लिया था। वह खाना नहीं बनाती थी। पौधों को पानी नहीं देती थी। शादी से पहले हमारे घर भी आई थी। ऐसे कौन अपने होने वाले ससुराल में

आता है। वह अस्सी किलो की थी। उसे सीढ़ियों से उतारना कितना मुश्किल था। मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह गोल्ड डिगर यानी कि पैसे की लालची थी। उसने मुझे दादी होने का सुख नहीं दिया।

ये बातें कोई ग्रामीण स्त्री नहीं कह रही है, एक रिटायर्ड जज कह रही है। सोचिए कि यदि इनके कोर्ट में ऐसे मुकदमे आते होंगे, तो इनका निर्णय क्या होता होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत से निर्णय कहते हैं कि स्त्री अगर बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती, तो उसके फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। शरीर उसका है, उस पर उसी का अधिकार है। यह भी कि आप पत्नी लाते हैं, कोई मेड नहीं कि खाना न बनाना तलाक का कारण बन सके।

त्विशा पैसे कमाती थी। नोएडा से भोपाल जाने पर उसके बहुत से काम छूट गए थे। इस पर भी उसे ताने सुनने पड़ते थे। यानी कि एक स्त्री पैसे कमाए, उसे अपने पति के परिवार को सौंप दे। घर का काम करे। खाना बनाए। सबकी सेवा करे। किसी और से कभी बातचीत तक न करे, नहीं तो उसके चरित्र पर सवाल उठाने का अधिकार, हर ऐरे-गैरे नत्थू खैरे को मिल जाएगा। कई वकीलों ने कहा भी कि ये आरोप तो स्त्रियों पर सदा से लगते आए हैं।

सोचने की बात है कि शादी करते ही आखिर लड़कियों के ऊपर ही सारा बोझ क्यों लाद दिया जाता है। इन दिनों ऐसे वीडियोज और रील्स की भरमार है, जिनमें ऐसा न करने पर पत्नी को पति घर से निकालने और तलाक की धमकी देते पाए जाते हैं। एक तरफ तो ये वीडियोज समाज में फैली असलियत को बताते हैं, मगर दूसरी तरफ बहुत से लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करते होंगे। आखिर लड़कियां ही क्यों घर से निकाली जाएं। वे ही क्यों तरह-तरह के लांछन झेलें। यदि प्रतिवाद करें, तो मारी जाएं और यदि चुपचाप सहती रहें, तो खुद जान दे दें।

ग्रेटर नोएडा में रहने वाली दीपिका के पिता तो कुछ देर पहले ही उससे मिल कर गए थे। और कुछ ही देर में उसकी मौत की खबर आई। उसके भाई ने कहा कि अगर हमने बहन की सुनी होती और उसे घर ले आए होते, तो शायद बहन जिंदा होती। आम तौर पर लड़कियों के घर वालों की यही कहानी होती है। जो समाज उनकी परेशानियों में कभी कोई हिस्सा नहीं बंटाता, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, परिवार अपनी ही लड़कियों को वधिकों के हाथों छोड़ देते हैं। अपनी लड़कियों को ही सहने और एडजेस्ट करने की सीख देते हैं। आपकी लड़की की जान चली जाती है, समाज का कुछ नहीं जाता। त्विशा भी अपनी मां को बताती रही कि वह गलत जगह फंस गई है, लेकिन उसकी मां उससे कहती रही कि अपनी सास से बात करो। सब ठीक हो जाएगा। इन दोनों लड़कियों और इन जैसी बहुत-सी स्त्रियों की जान चली जाती है। यह बात भी महसूस होती है कि लड़कियां जैसे ही किसी घर की बहू बनती हैं, किसी की पत्नी कहलाती हैं, उनका जीवन गिरवी रख दिया जाता है। वे हमेशा किसी न किसी से दया मांगती रहे। एक ऐसा ऑडियो भी सामने आया है जिसमें त्विशा के भाई से बात करते हुए उसकी सास उसके चरित्र पर शक कर रही है। यह सास फिल्मों वाली ललिता पंवार नहीं है, लेकिन बहू की मौत पर मजाल है कि एक आंसू भी आया हो। बहू का मरना भी कोई मरना होता है। एक मरती है, दूसरी आ जाती है। जब यह लेखिका बहुत छोटी थी, दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, तब इसके पिता कन्नौज रेलवे स्टेशन पर पोस्टेड थे। उन दिनों घर लौटकर अक्सर वे इस बात की सूचना देते थे कि आज फलां ने अपनी तीसरी बहू मार दी कि एक और ने अपनी पत्नी को मार दिया और दस दिन बाद ही दूसरी शादी भी कर ली। फिर अपनी तीन बेटियों के लिए बहुत चिंतित भी होते। यह भी कहते कि दूसरी पत्नी के माता-पिता ये सवाल कभी क्यों नहीं पूछते कि पहली पत्नी कैसे मरी। यदि पूछते होते, तो शायद ऐसे घर में अपनी बेटी को कभी न देते। आज भी बेटियों की तो किस्मत में ही ये लिखा है कि अपने घरों में वे जन्म से पहले ही भाई की चाहना में प्राण गंवाएं और ससुराल चली जाएं, तो न जाने कितने आरोप और वधिक उनके लिए तलवार लिए बैठे हैं।

यों भी क्या बेटी पालने में बेटे पालने के मुकाबले, कम संसाधन खर्च होते हैं। इन दिनों जब शहरी परिवारमात्र एक-दो बच्चों तक ही सीमित हैं, तब बेटियों की शिक्षा-दीक्षा पर भी बेटे की तरह ही खर्च होता है, लेकिन अब भी वे दोयम दर्जे की नागरिक हैं। नारा लगाते रहिए कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ।

क्षमा शर्मा

ऊर्जा की नई किरण भारत-ओमान समुद्री पाइप लाइन

होर्मुज जलसंधि का रास्ता बंद होने और भारत में ऊर्जा-संकट के बादल गहराने से जुड़ी खबरों के बीच एक खबर को ज्यादा सुर्खियां नहीं मिल पाईं कि भारत, गहरे समुद्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना पर विचार कर रहा है, जो हमें ओमान से जोड़ेगी। भारत सरकार ने अब इस पर तेजी से काम करना शुरू किया है।

हाल में कुछ मीडिया स्रोतों ने पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारियों को उद्धृत करते हुए खबर दी है कि मंजूरी मिली, तो करीब 4.8 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली परियोजना खाड़ी क्षेत्र से निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। परियोजना को समय से हरी झंडी मिली, तब भी इसे पूरा होने में पांच से सात साल लगेंगे। उसके पहले इसके सभी आर्थिक और तकनीकी पहलुओं पर विचार करना भी जरूरी होगा।

सौ साल से ज्यादा समय से इसकी परिकल्पना चल रही है। इस पर यूपीए सरकार के दौर में भी बात चली थी। ओमान की वेबसाइट 'मस्कट डेली' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार नई दिल्ली स्थित निजी क्षेत्र के कंसोर्शियम साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज (सेज) द्वारा प्रस्तुत पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पर विचार कर रही है, जो समुद्र तल की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए 'टेस्ट-सेक्शन' बिछा रहा है।

'सेज' ने प्रस्तावित मार्ग पर लगभग 3,000 मीटर परीक्षण पाइपलाइन बिछाकर प्रारंभिक चरण का तकनीकी सत्यापन कर लिया है, जिस पर लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह पाइपलाइन इंजीनियरों के लिए चुनौती भी होगी, क्योंकि कुछ जगहों पर यह करीब साढ़े तीन किलोमीटर तक की गहराई पर बिछानी पड़ेगी, जो अब तक समुद्र के नीचे बिछाई गई दुनिया की किसी भी पाइपलाइन की तुलना में चार गुना अधिक गहरी होगी।

इस अध्ययन का उद्देश्य समुद्र तल की स्थितियों का आकलन करना और इंजीनियरिंग संभावनाओं की पुष्टि करना है। संभावना है कि भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय, सरकारी कंपनियों गेल, इंजीनियर्स इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देगा। रिपोर्ट सकारात्मक हुई, तो ओमान के साथ गैस आपूर्ति, वित्तपोषण और परियोजना कार्यान्वयन पर औपचारिक बातचीत का रास्ता खुलेगा।

पश्चिम एशिया से भारत तक समर्पित पाइपलाइन बनी, तो हम किसी ट्रांजिट देश या समुद्री अवरोध बिंदु पर निर्भर नहीं रहेंगे और किफायती लागत पर गैस की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी। मिडिल-ईस्ट-इंडिया डीप-वाटर पाइपलाइन (एमईआईडीपी) अरब सागर के नीचे लगभग 2,000 किलोमीटर तक लंबी होगी, जो ओमान को भारत के गुजरात तट से जोड़ेगी। इस परियोजना से भारत को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से गैस आपूर्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

वर्ष 2025 में भारत के एलएनजी आयात का लगभग दो-तिहाई हिस्सा होर्मुज जलसंधि से होकर गुजरा था। इस साल फरवरी के अंत में होर्मुज संकट शुरू होने के बाद, वैश्विक एलएनजी आपूर्ति में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जिससे कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। इस गिरावट के कारण भारत के उर्वरक संयंत्रों, बिजलीघरों और उद्योगों की आपूर्ति में अचानक लगे झटकों ने चिंता पैदा की है। खनिज तेल की ऊंची कीमतों ने आयात लागत को पहले ही बढ़ा दिया है।

इस पृष्ठभूमि में, टैंकरों पर निर्भरता को कम करने और प्राकृतिक गैस का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए दशकों पुरानी इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 31 मिलियन मानक घन मीटर (एमएमएससीएमडी) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होने की उम्मीद है। वर्तमान राष्ट्रीय गैस खपत लगभग 190 से 195 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन है, जो औद्योगिक और शहरी गैस नेटवर्क के विस्तार और उर्वरक क्षेत्र की मांग में वृद्धि पर भी निर्भर है। 2030 तक, यह मांग 290 से 300 मिलियन वर्ग मीटर प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान है।

भारत को खाड़ी देशों से जोड़ने वाली समुद्री पाइपलाइन की अवधारणा नई नहीं है। 1990 के दशक से इस प्रस्ताव के विभिन्न रूप समय-समय पर सामने आते रहे हैं, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता की जटिलता, वित्तपोषण की अनिश्चितता और अपर्याप्त राजनीतिक उत्साह के कारण वे ठंडे बस्ते में चले गए। बहरहाल इसबार की पहल तीन कारणों से उत्साहवर्धक है। एक, समुद्र में पाइप बिछाने की तकनीक में काफी प्रगति हुई है। पर्याप्त भू-राजनीतिक झटकों की वजह से राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा हो गई है, और तीसरे, सरकारी संस्थाओं को काम के औपचारिक निर्देश मिले हैं। यह परियोजना अब केवल सैद्धांतिक मनोकामना नहीं है, बल्कि सक्रिय इंजीनियरिंग और डिप्लोमैटिक प्रयास है।

इस पाइपलाइन की संरचना से भारत को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से प्राकृतिक गैस प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। इन देशों के पास सामूहिक रूप से लगभग 2,500 ट्रिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस का भंडार है। कतर के पास लगभग 868 ट्रिलियन घन फुट और ईरान के पास लगभग 1,649 ट्रिलियन घन फुट का भंडार है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा की तुलना चीन से करें, तो पाएंगे कि चीन ने अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ समय रहते उठा लिया है। भारत, जहां लगभग पूरी तरह से समुद्री पोतों से आने वाली एलएनजी पर निर्भर है, वहीं चीन ने व्यवस्थित रूप से भूमि और क्षेत्रीय पाइपलाइन गलियारों का एक नेटवर्क बना लिया है। इसके कारण वह होर्मुज पाइपलाइन के व्यवधान से काफी हद तक सुरक्षित हो गया है।

चीन की पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन, जो दिसंबर, 2019 से चालू है, पूरी क्षमता से रूस के साइबेरिया गैस क्षेत्रों से प्रति वर्ष 38 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) तक गैस की आपूर्ति करती है। उसकी दूसरी पाइपलाइन, पावर ऑफ साइबेरिया 2 है, जिसकी प्रस्तावित क्षमता 50 बीसीएम प्रति वर्ष है। वह मंगोलिया से होकर आएगी, पर अभी उसपर बातचीत चल रही है।

इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान से चीन का मध्य एशियाई पाइपलाइन नेटवर्क, तीन समानांतर लाइनों के माध्यम से 55 बीसीएम प्रति वर्ष गैस की ढुलाई करता है। चौथी लाइन निर्माणाधीन है जो कुल क्षमता को 85 बीसीएम प्रति वर्ष तक बढ़ा देगी।

भारत और चीन की भंडारण क्षमता में बड़ा अंतर है। भारत में 22 से 24 एलएनजी भंडारण टैंकों में लगभग 2 से 2.5 अरब घनमीटर गैस का भंडार है, जो राष्ट्रीय गैस खपत के 10 से 12 दिनों के बराबर है। वहीं, चीन 2026 के अंत तक लगभग 80 अरब घनमीटर भंडारण क्षमता हासिल करने की राह पर है , जो उसकी वार्षिक खपत का लगभग 20 प्रतिशत है।

प्रमोद जोशी

अतीत में पाकिस्तान के रास्ते तुर्कमेनिस्तान और ईरान से पाइपलाइनें बिछाने की परियोजनाओं पर काम हुआ था, पर वे बन नहीं पाईं। भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चुनौतियों के कारण दशकों से प्रस्तावित 1800 किलोमीटर लंबी तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान, पाकिस्तान-इंडिया (तापी) पाइपलाइन नहीं बन पाई। यह पाइपलाइन करीब 33 अरब घनमीटर गैस का परिवहन करती।

दूसरी पाइपलाइन थी ईरान-पाकिस्तान-इंडिया (आईपीआई) लाइन। भारत ने भू-राजनीतिक कारणों और अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में खुद को इस परियोजना से लगभग अलग कर लिया।

भारत ने खनिज तेल का एक दीर्घकालीन भंडार ढांचा बना लिया है, पर गैस-भंडारण की विशाल अवसंरचना मौजूद नहीं है। अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और पश्चिम एशिया की लड़ाई के कारण, हमारी ऊर्जा सुरक्षा, जोखिम में पड़ गई है। यह पाइपलाइन आशा की एक किरण बन सकती है।

मटकी फोड़कर सड़कों पर उतरी जनता

माही की गूंज, शाजापुर/मक्सी।

जिले में भीषण गर्मी के बीच जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। कई गांवों और नगरों में लोग पेयजल के लिए परेशान हैं। टैंकरों पर निर्भरता बढ़ रही है, जबकि प्रशासन जल आपूर्ति बनाए रखने के प्रयासों में जुटा हुआ है। लगातार गहराते जल संकट ने मक्सी नगर में लोगों का सब्र तोड़ दिया।

पानी की समस्या को लेकर नगरवासियों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया, जब कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग नगर परिषद कार्यालय पहुंच गए। महिलाओं ने खाली मटके सिर पर रखकर प्रदर्शन किया और बाद में मटकियां फोड़कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई।

लगातार बढ़ रहा पेयजल संकट

नगर में पिछले कई दिनों से पेयजल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कई वार्डों में दो से तीन दिन तक पानी की सप्लाई नहीं हो रही, जिससे लोगों को टैंकरों के भरोसे दिन काटने पड़ रहे हैं। सुबह से ही पानी भरने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। महिलाओं और बच्चों को दूर-दूर तक पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।

कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए

लोगों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद नगर परिषद केवल आश्वासन दे रही है, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा। प्रदर्शन के दौरान नगर परिषद परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। आक्रोशित लोग परिषद कार्यालय के अंदर जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाद में प्रदर्शनकारी परिषद कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की।

आश्वासन नहीं, बल्कि पानी चाहिए

मक्सी ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष मेहरबान सिंह पटेल ने नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन चरम पर है। जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी संवेदनहीन बने हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी।

प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का विरोध सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। महिलाओं ने खाली मटकी फोड़कर अपनी पीड़ा जताई। इतना ही नहीं, मौके पर खड़े पानी के टैंकर से पानी पीकर उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि नगर में हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। यह दृश्य देखकर आसपास मौजूद लोग भी भावुक नजर आए।

नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों के अवकाश पर होने के कारण प्रदर्शनकारियों ने नायब तहसीलदार जितेंद्र चौरसिया को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लोगों को जल्द समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। हालांकि नगरवासियों का कहना है कि अब उन्हें आश्वासन नहीं, बल्कि पानी चाहिए।

चीलर डेम में बचा सिर्फ दो फीट से कम पानी

शाजापुर क्षेत्र के लिए राहत का प्रमुख स्रोत माने जाने वाले चीलर डेम में अब केवल करीब दो फीट से कम पानी बचा है। लगातार बढ़ती गर्मी और पानी की अधिक खपत के कारण जलस्तर तेजी से नीचे पहुंच गया है। यदि जल्द वर्षा नहीं हुई तो आने वाले दिनों में जल संकट और गंभीर हो सकता है।

प्रशासन पानी की सप्लाई बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार कर रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है। जल विशेषज्ञों का मानना है कि अभी से पानी बचाने और बर्बादी रोकने के प्रयास नहीं किए गए तो कई क्षेत्रों में पेयजल संकट विकराल रूप ले सकता है।

आरटीई में प्रवेश नहीं मिलने पर मासूम बच्चों का प्रदर्शन

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) योजना के तहत स्कूल प्रवेश नहीं मिलने से नाराज पालकों और बच्चों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया। करीब 40 डिग्री तापमान के बीच छोटे-छोटे बच्चे छाता लेकर अपने माता-पिता के साथ प्रदर्शन करते नजर आए।

मामला सेंट थॉमस स्कूल में नर्सरी प्रवेश से जुड़ा है। पालकों का आरोप है कि आरटीई योजना के तहत ऑनलाइन लॉटरी में चयन होने के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया।

प्रदर्शन कर रहे पालकों ने बताया कि, सत्र 2026-27 के लिए उनके बच्चों का चयन ऑनलाइन प्रक्रिया में हुआ था और 15 अप्रैल 2026 तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का संदेश भी प्राप्त हुआ था, लेकिन जब वे स्कूल पहुंचे तो प्रवेश देने से मना कर दिया गया। बाद में आवंटन निरस्त होने का संदेश भी भेज दिया गया।

पालकों का कहना है कि वे इस मामले को लेकर कलेक्टर कार्यालय, जनसुनवाई और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 तक शिकायत कर चुके हैं। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी मुलाकात की गई, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला।

मंगलवार सुबह करीब 11रू30 बजे बड़ी संख्या में बच्चे और उनके अभिभावक कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इस दौरान तहसीलदार, एसडीएम और अपर कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पालक अपनी मांग पर अड़े रहे।

बाद में कलेक्टर ने जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर और कुछ पालकों को चर्चा के लिए बुलाया। करीब आधे घंटे चली बैठक के बाद दीपक सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है।

उन्होंने बताया कि अब आरटीई प्रवेश प्रक्रिया को ऑफलाइन माध्यम से पूरा कराने की तैयारी की जा रही है। कलेक्टर ने कुछ स्कूलों की सूची पर भी चर्चा की और समाधान के लिए करीब 10 दिन का समय मांगा है। पालकों को आश्वासन दिया गया कि संबंधित स्कूलों में आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश दिलाया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद दोपहर करीब पौने दो बजे धरना समाप्त कर दिया गया।

सड़क किनारे निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के पिपलिया मंडी क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए सड़क किनारे बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अमला और पुलिस बल बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहा। पिपलिया मंडी में मुख्य सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे बने अवैध निर्माण, अस्थायी ढांचे और कब्जों को हटाना शुरू किया।

अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था और लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अभियान का उद्देश्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त कर सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

कार्रवाई के दौरान कई दुकानों और निर्माणों को हटाया गया। प्रशासन की टीम ने जेसीबी और बुलडोजर की मदद से अवैध ढांचों को तोड़ा। इस दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा।

स्थानीय व्यापारियों और लोगों में कार्रवाई को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई को उचित बताया, जबकि कुछ प्रभावित लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था और पूर्व सूचना को लेकर सवाल उठाए।

प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों को पहले नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें निर्धारित समय में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कब्जे नहीं हटाए जाने पर कार्रवाई की गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बढ़ते शहरों और कस्बों में अतिक्रमण बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इससे यातायात, सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं पर असर पड़ता है। ऐसे में प्रशासन समय-समय पर अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास करता है।

राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर बहस होती रहती है। कई बार प्रभावित लोग पुनर्वास या वैकल्पिक स्थान की मांग करते हैं, जबकि प्रशासन नियमों के पालन को प्राथमिकता देता है।

फिलहाल पिपलिया मंडी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

7 वर्ष बाद देश विरोधी पोस्ट करने वाले आरोपी को मिली सजा

माही की गूंज, शाजापुर। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद शाजापुर निवासी मोहसीन लाला ने फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने के साथ ही बहनों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। मामले में हिंदू संगठन से जुड़े रोहित राठौर की शिकायत पर केस दर्ज कर मोहसीन को गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में न्यायालय ने आरोपित मोहसीन को दो वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा दी है।

जिला मीडिया सेल प्रभारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी रोहित राठौर ने 16 फरवरी 2019 को थाना कोतवाली शाजापुर में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि श्मोहसिन लालाश् नाम की फेसबुक आईडी से श्पाकिस्तान जिंदाबादश् के नारे के साथ अश्लील शब्दावली का प्रयोग करते हुए एक पोस्ट डाली थी।

पोस्ट से राष्ट्रीय भावनाएं आहत होने की बात कही और कार्रवाई की मांग की गई। न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपित को दोषी पाया गया। मामले में शासन की ओर से पैरवी प्रतीक श्रीवास्तव और तुलसी मानकर ने की।

मोहसीन द्वारा की गई पोस्ट से लोगों में आक्रोश फैल गया था। अभिभाषकों ने आरोपित ओर से पैरवी करने से इनकार कर दिया। स्थिति यह बनी की आरोपित की तरह से वकील खड़ा नहीं हुआ था। दरअसल हिंदू संगठन और गौरक्षा टीम ने मामले में अभिभाषक संघ को ज्ञापन देकर आरोपित की पैरवी नहीं करने का आग्रह किया था। इस पर संघ ने भी पैरवी नहीं करने की घोषणा की थी। इसके आरोपित के कृत्य के खिलाफ रैली निकालकर आजाद चौक में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था।

आरोपित द्वारा देश विरोधी कमेंट किए जाने के मामले में प्रदेश की प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों ने भी संज्ञान लिया था। बाहर की सुरक्षा एजेंसी की टीम ने भी शाजापुर कोतवाली थाना पहुंच कर आरोपित से पूछताछ की थी। इस दौरान आरोपित ने कुछ संगठनों के नाम भी बताए थे, जिनसे वह परिचित था।

न्याय ना मिलने पर किसान ने खुद पर डाला पेट्रोल

माही की गूंज, रतलाम।

मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक नाराज किसान ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। किसान का आरोप है कि तीन साल पहले उसने अपनी तीन बीघा जमीन पर लहसुन और दो बीघा जमीन पर प्याज की फसल बोई थी।

तीन साल पहले दर्ज कराई थी शिकायत, आज तक सुनवाई नहीं

इसी दौरान किसान ने डाक के माध्यम से एक कंपनी से फसल में उपयोग होने वाली दवाई मंगाई थी, लेकिन दवाई का इस्तेमाल करने के चार दिनों के भीतर ही उसकी पूरी फसल खराब हो गई। किसान का कहना है कि उसने इस मामले की शिकायत तीन साल पहले कलेक्टर कार्यालय में दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वह लगातार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला।

अधिकारियों से परेशान होकर उठाना पड़ रहा आत्महत्या का कदम

किसान ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा जांच टीम भी बनाई गई थी, जिसने जांच के बाद भी संबंधित दवा कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की। आर्थिक तंगी और लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने से परेशान होकर वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो गया। वहीं रतलाम की एडीएम शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि किसान जनसुनवाई के निर्धारित समय के बाद कार्यालय पहुंचा था। इसी दौरान तेज आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी मिली।

उन्होंने कहा कि कलेक्टर उस समय मौके पर मौजूद नहीं थीं। एडीएम के अनुसार किसान की शिकायत पहले भी सुनी जा चुकी है, लेकिन उस समय ऐसे मामलों में मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने बताया कि किसान ने उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत दर्ज कराई है और अब वहीं से उसकी समस्या का समाधान संभव हो सकेगा।

9 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 9 साल की बच्ची के साथ दो दरिंदों ने बर्बरता की। आरोपियों ने बच्ची को कंचे देने का लालच देकर अपने पास बुलाया और फिर एक बंद कमरे में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घिनौने कृत्य में 25 वर्षीय अजय उर्फ विजय मालवीय और 40 वर्षीय अशोक दर्जी शामिल थे।

घटना उस समय हुई जब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। अजय ने उसे अकेला देखकर एक अन्य बच्चे को बुलाया और कहा कि उसे कंचे दिए जाएंगे। जैसे ही बच्ची उनके पास पहुंची, दोनों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।

परिवार की प्रतिक्रिया और पुलिस कार्रवाई

घटना के बाद, आरोपियों ने बच्ची को धमकी दी कि वह किसी को कुछ नहीं बताए। जब बच्ची अपने घर पहुंची और अपनी मां को सब कुछ बताया, तो परिवार में हड़कंप मच गया। तुरंत ही उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, एसपी विनोद कुमार मीना ने पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है और लोग आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

वेब सीरीज से सीखा फिरौती मांगने का तरीका

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में एक व्यापारी से 15 लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज से प्रभावित होकर पूरी साजिश रची थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी तकनीकी तरीके अपनाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोबाइल ट्रैकिंग और सतर्क पुलिस कार्रवाई के चलते वह गिरफ्त में आ गया।

पुलिस के अनुसार, 19 मई को व्यापारी तैय्यब अली निवासी नई अभिनंदन ग्रीन वैली, मंदसौर ने जनसुनवाई के दौरान शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें मोबाइल कॉल के जरिए पहले 5 लाख और बाद में 15 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। रकम नहीं देने पर गोली मारने की धमकी भी दी गई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने फरियादी को समझाइश दी कि यदि आरोपित दोबारा कॉल करे तो बातचीत जारी रखें, ताकि तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा सकें। इसी रणनीति के तहत आरोपित ने दोबारा कॉल कर धमकी दी और 15 लाख रुपये की मांग दोहराई।

तकनीकी जांच और मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस ने आरोपित रेहान पुत्र कल्लू खां (20) निवासी खिलचीपुरा, मंदसौर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बाइक, स्मार्टफोन, कीपैड मोबाइल और सिम कार्ड जब्त किए गए हैं।

शनिवार को कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि आरोपित बीए सेकंड ईयर का छात्र है और कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) की तैयारी भी कर रहा है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने ष्शूटआउट एट लोखंडवालाष् सहित कई बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज देखकर फिरौती मांगने का तरीका सीखा था। वह सोशल मीडिया पर अपराध और धमकी से जुड़ी रील्स भी देखता था।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित करीब तीन-चार साल पहले व्यापारी के निर्माणाधीन मकान में एसी फिटिंग के काम से गया था। तभी उसने व्यापारी को निशाना बनाने की योजना बना ली थी। उसने सात महीने पहले अलग से एक कीपैड मोबाइल खरीदा, जिसका इस्तेमाल केवल अपराध के लिए करना चाहता था।

आरोपी ने उज्जैन-इंदौर ट्रेन यात्रा के दौरान एक यात्री के मोबाइल से सिर्फ सिम कार्ड चोरी किया था, ताकि शिकायत की संभावना कम रहे। साथ ही उसने एक मजदूर को नौकरी दिलाने का लालच देकर उसके नाम से दूसरा सिम कार्ड भी खरीद लिया था।

कोट बामनी में बूंद-बूंद पानी के लिए जूझ रहे ग्रामीण

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले की सेमलेट ग्राम पंचायत के कोट बामनी गांव में गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के ग्रामीण प्रतिदिन तीन से चार किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। बुधवार सुबह भी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तड़के 3 बजे खाली बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकल पड़े।

ग्रामीण नकारसिंह सोलंकी ने बताया कि लगभग 840 की आबादी वाले गांव में 500 से अधिक लोग पानी की भारी समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीण अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के सहारे कुओं और छोटे जल स्रोतों से पानी भरकर घर तक पहुंचाते हैं। गांव में लगे दो हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़े हैं।

गांव के दोनों प्राकृतिक कुओं का पानी भी पीने योग्य नहीं बचा है। कुओं में काई जम गई है तथा मच्छरों के लार्वा पनपने से पानी दूषित हो चुका है। ग्रामीण गोटिया सोलंकी ने बताया कि मजबूरी में लोग इसी दूषित पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। पानी की कमी इतनी गंभीर है कि कई परिवार सप्ताह में केवल एक बार ही स्नान कर पा रहे हैं। दैनिक जरूरतों के लिए भी पानी का उपयोग बेहद सावधानी से करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या से सबसे अधिक परेशानी महिलाओं और बच्चों को हो रही है। उन्हें अन्य कार्य छोड़कर सबसे पहले पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। ग्रामीण रेंजला ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

ग्रामीणों के अनुसार हर वर्ष गर्मी के मौसम में यही स्थिति बन जाती है। लोगों को रात 3 बजे उठकर कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पेयजल समस्या को लेकर पीएचई विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन केवल आश्वासन देता है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही। नर्मदा किनारे बसे गांव में लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिए रात में भटकना पड़ रहा है, जिससे विकास के दावों पर सवाल उठ रहे हैं।

पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री आर.एस. बामनिया ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। विभाग की टीम को जांच के लिए भेजा जाएगा तथा जांच के बाद समस्या के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गांव से लगभग 500 मीटर दूर एक हैंडपंप चालू स्थिति में है।

हथियारबंद बदमाशों ने लूटी शराब से भरी पिकअप

माही की गूंज, बड़वानी।

बड़वानी-पाटी मार्ग पर बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात अज्ञात बदमाशों ने शराब से भरी पिकअप वाहन को हथियारों के बल पर लूट लिया। घटना बड़वानी खुर्द के पास बावनगजा मार्ग पर हुई। बदमाशों ने इंदौर से पाटी जा रही पावर कूल बियर की 222 पेटियों से भरे वाहन को निशाना बनाया। शराब दुकान संचालक हुकुम राठौड़ ने बताया कि उनकी पाटी स्थित दुकान के लिए इंदौर वेयरहाउस से पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 46 जेडएच 2310 में 222 पेटी पावर कूल बियर भेजी गई थी। शराब की अनुमानित कीमत करीब पांच लाख रुपये बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार रात करीब 2रू30 बजे बड़वानी खुर्द के आगे बावनगजा मार्ग पर 30 से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने पिकअप वाहन को घेर लिया। बदमाशों ने चालक को पिस्टल दिखाकर धमकाया और शराब से भरी पिकअप लेकर जंगल की ओर फरार हो गए। चालक ने तत्काल वाहन मालिक और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बड़वानी खुर्द से ग्वालबेड़ा तक जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया। देर रात ग्वालबेड़ा के पास तालाब किनारे लावारिस हालत में लूटी गई पिकअप बरामद कर ली गई। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर वैज्ञानिक जांच शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है तथा बावनगजा मार्ग और पाटी रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिलेभर में नाकेबंदी कर वाहनों की जांच भी की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र के शराब ठेकेदारों में भय का माहौल है। ठेकेदारों ने रात के समय शराब परिवहन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित कर दी है। फिलहाल पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपियों की तलाश कर रही है।

जिला सहकारी बैंक की शाखा में 41 लाख रुपये का गबन उजागर

माही की गूंज, खरगोन।

खरगोन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठिबगांव शाखा में 41 लाख 58 हजार रुपये के गबन का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में नगद राशि में कमी पाए जाने के बाद कैशियर रितु गोयल और सहायक गणक त्रयम्बक वाणी को निलंबित कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक प्रबंधन ने जैतापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

बैंक की मुख्य कार्यपालन अधिकारी संध्या रोकड़े ने बताया कि 25 मई को शाखा में नियमित नगद मिलान और भौतिक सत्यापन के दौरान अनियमितता उजागर हुई। जांच में वास्तविक नगद शेष राशि और अभिलेखों में दर्ज राशि के बीच 41 लाख 58 हजार 95 रुपये का अंतर पाया गया।

बैंक सूत्रों के अनुसार कैशियर रितु गोयल सोमवार दोपहर बाद बिना किसी सूचना के शाखा से अनुपस्थित हो गईं। उनके मोबाइल फोन भी बंद मिले। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर शाखा में पंचनामा तैयार कराया।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि शाखा स्तर पर नगद हस्तांतरण और संयुक्त निरीक्षण से संबंधित निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। इसी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी राशि एक ही कर्मचारी के पास बनी रही। बैंक प्रबंधन ने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि उनके हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। मामले की विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।

विधायक ने जिला पंचायत सीईओ पर लगाए अवैध वसूली के आरोप

माही की गूंज, बड़वानी।

बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में विधायक मोंटू सोलंकी ने जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी काजल जावला पर पंचायत सचिवों से अवैध वसूली करने के आरोप लगाए हैं। विधायक ने यह आरोप ग्राम पाड़छा के दौरे के दौरान ग्रामीणों के बीच लगाए। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई।

विधायक सोलंकी ने कहा कि जिला पंचायत सीईओ पंचायत सचिवों को निलंबन की धमकी देकर उनसे 10-10 लाख रुपये की मांग कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों के दौरे और बैठकों की जानकारी भी उन्हें नहीं दी जाती।

ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए विधायक ने क्षेत्र में पेयजल, खराब सड़कें और पुल-पुलियों की समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान के बजाय अधिकारी मनमानी और वसूली में व्यस्त हैं। विधायक ने प्रशासन की कार्यप्रणाली को तानाशाहीपूर्ण बताया।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है।

जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी काजल जावला ने विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पाड़छा में आयोजित गंगा दशहरा के शासकीय कार्यक्रम में विधायक को विधिवत आमंत्रित किया गया था। उनके अनुसार एक जनपद क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं और हर कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति संभव नहीं होती।

काजल जावला ने कहा कि जिला पंचायत का प्रभार उनके पास है, इसलिए पंचायतों का निरीक्षण और समीक्षा बैठकें करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने इस आरोप को भी खारिज किया कि समीक्षा बैठकें विधायक की अनुमति से ही आयोजित की जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि जिस पंचायत में विधायक पहुंचे थे, वहां के एक सचिव को कार्रवाई के तहत निलंबित किया गया है। उनके अनुसार जल गंगा अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्य पूरा हुए बिना भुगतान प्रमाणित कर दिया गया था। इस मामले में सरपंच और जीआरएस को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

सीईओ ने कहा कि संभवतः इसी कार्रवाई के बाद पंचायत प्रतिनिधियों ने विधायक से संपर्क किया होगा, जिसके चलते यह विवाद सामने आया है।

जनगणना कार्य में लगे 60 हजार शिक्षकों में नाराजगी

माही की गूंज, खरगोन।

प्रदेश में जनगणना कार्य में लगे करीब 60 हजार शिक्षकों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। 31 मई को शिक्षकों की छुट्टियां समाप्त हो रही हैं, जिसके बाद उन्हें विद्यालयों में उपस्थित होना होगा। राज्य शिक्षक संघ ने भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षकों की छुट्टियां 15 जून तक बढ़ाने तथा नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू करने की मांग की है। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ऐसी स्थिति में विद्यालयों में पर्याप्त बिजली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव में शिक्षकों को बुलाना उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। संघ का कहना है कि शासन द्वारा विद्यार्थियों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां 15 जून तक घोषित की गई हैं, जबकि शिक्षकों की छुट्टियां 31 मई तक सीमित कर दी गई हैं। इस असमान व्यवस्था के कारण शिक्षकों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। खरगोन जिले में भी लगभग 1200 शिक्षक जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। राज्य शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों को भी विद्यार्थियों के साथ 15 जून के बाद ही विद्यालय बुलाया जाए, ताकि वे भीषण गर्मी से सुरक्षित रहकर नए शैक्षणिक सत्र की बेहतर तैयारी कर सकें।

बढ़ती गर्मी नहीं, ये है भविष्य की भयावह चेतावनी

बदलती जलवायु के कारण भारत सहित दुनिया के अनेक हिस्से भीषण हीट वेव की चपेट में है। अब यह संकट पारंपरिक क्षेत्रों से निकलकर तटीय इलाकों तक फैल चुका है। अंधाधुंध शहरीकरण, घटती हरियाली और कंक्रीट के बढ़ते निर्माण से 'अर्बन हीट आइलैंड' का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे दिन और रातें अत्यधिक गर्म हो रही हैं। राजस्थान के बाड़मेर से लेकर दिल्ली की गलियों और विदर्भ के मैदानों तक पारा 45 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर चुका है। यह केवल बढ़ते तापमान का आंकड़ा नहीं है बल्कि यह एक गहराता सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और आर्थिक चेतावनी है। हीट वेव अब केवल मौसमी असुविधा नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और मानव अस्तित्व के लिए गंभीर संकट बन चुकी है। बढ़ते तापमान, घटती हरियाली और कंक्रीट के फैलते जंगलों ने जीवन को लू की लपटों में समेट दिया है।

मौसम विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ताजा आंकड़ों ने एक डरावनी तस्वीर पेश की है। पिछले चार दशकों में हीट वेव (लू) से होने वाली मौतों में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि हीट वेव अब केवल अपने पारंपरिक गढ़ (उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत) तक सीमित नहीं रही बल्कि इसने दक्षिण भारत के उन तटीय इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जो ऐतिहासिक रूप से कम ताप प्रभावित रहते थे। अध्ययन बताते हैं कि 1981 से 2000 के बीच लू की औसत अवधि जहां 2.5 से 5.5 दिन थी, वहीं 2001 से 2020 के बीच यह बढ़कर 8.5 दिन तक पहुंच गई। लू का भौगोलिक दायरा भी 11.9 लाख वर्ग किलोमीटर से फैलकर 18.1 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। यह विस्तार बताता है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान की कड़वी हकीकत है। हमारे शहर कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो चुके हैं, जो दिनभर गर्मी सोखते हैं और रात में उसे मुक्त करते हैं, जिससे 'अर्बन हीट आइलैंड' का प्रभाव पैदा होता है। इस तपती आग में सबसे अधिक जोखिम उन लोगों (रेहड़ी-पटरी वाले, निर्माण श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर) का है, जो खुले आसमान के नीचे अपना वजूद तलाशते हैं। इनके पास न तो कूलिंग सेंटर की सुविधा है और न ही काम के घंटों में लचीलापन। इसके साथ ही बच्चे और बुजुर्ग इस बढ़ते 'डिस्कंफर्ट इंडेक्स' के सबसे आसान शिकार बन रहे हैं।

वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में वृद्धि से आगामी वर्षों में हीट वेव, गर्मी का मौसम ज्यादा समय तक रहने और सर्दी के मौसम का समय घटने जैसी स्थितियां पैदा होंगी। इस बारे में वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि जिस जलवायु परिवर्तन के बारे में अब तक हम केवल पढ़ते-सुनते रहे थे, वह अब हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। भारत में मई का महीना गर्म हवाओं (लू) का चरम समय होता है और लू की घटनाओं को भी मौसम में दिन-प्रतिदिन बदलाव का स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है लेकिन चिंता की बात यही है कि लू की तीव्रता लगातार वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। पिछले करीब डेढ़ दशकों में 2009, 2010, 2016, 2017 और 2022 भारत में रिकॉर्ड किए गए पांच सबसे गर्म वर्ष रहे। आईएमडी के मुताबिक 15 सबसे गर्म वर्षों में से 11 वर्ष 2008 से 2022 के बीच ही दर्ज किए गए।

यह जानना भी जरूरी कि हीट वेव आखिर है क्या? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि है, जो प्रायः दो या ज्यादा दिनों तक रहती है। जब तापमान किसी क्षेत्र के सामान्य औसत तापमान से अधिक हो जाता है तो उसे 'हीट वेव' कहा जाता हं। आईएमडी के अनुसार मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान जब 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चलने लगती है और यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो यह खतरनाक लू की श्रेणी में कही जाती है। इसी प्रकार तटीय क्षेत्रों में जब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो लू चलने लगती है। हीट वेव के कारण लोगों के बीमार होने और हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है तथा सैंकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1998 से 2017 के बीच हीट वेव के कारण 1.66 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और यह आंकड़ा अब वर्ष दर वर्ष तेजी से बढ़ रहा है।

आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन से यह स्पष्ट हो चुका है कि तापमान में वृद्धि तथा लू का मानव शरीर पर व्यापक असर पड़ रहा है। गर्म हवाओं से ब्रेन स्ट्रोक, हृदयाघात, नसों में खून के थक्के जमने की आशंका, स्थायी विकलांगता का खतरा बढ़ जाता है और इससे मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, हीट वेव बाढ़ के बाद दूसरी सबसे घातक आपदा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रही है। लू का असर हृदय तथा फेफड़े जैसे अंगों पर सर्वाधिक पड़ता है, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। हीट वेव से ऐसे लोगों की स्थिति और खराब होने की संभावना होती है, जो हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी इत्यादि समस्याओं से पीड़ित हैं। आईएमडी के मुताबिक वैसे तो हर साल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य, पूर्व और उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के मैदानी इलाकों में मार्च से जून के दौरान हीट वेव का दौर चलता है लेकिन जैसे-जैसे पृथ्वी की जलवायु गर्म होती जा रही है, दिन और रात भी सामान्य से अधिक गर्म होते जा रहे हैं, जिससे हीट वेव की घटनाएं बढ़ रही हैं और मौतों तथा बीमारियों की आशंका भी बढ़ रही है।

प्रश्न यह है कि भारत में हीट वेव को लेकर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? पिछले 30 वर्षों के तापमान तथा गर्म हवाओं का आकलन करते हुए आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया था कि घटती हरियाली, शहरीकरण तथा कंक्रीट से निर्माण के कारण ही अब प्रतिवर्ष हीट वेव में वृद्धि हो रही है। प्रायः देखा जाता है कि एक ही शहर में कुछ जगहों पर उच्च तापमान दर्ज किया जाता है तो कुछ जगहों पर तापमान कम रहता है। कुछ स्थानीय कारण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। दरअसल अधिक हरे-भरे इलाकों में तापमान कम दर्ज किया जाता है जबकि चारों ओर बसी कालोनियों तथा ऊंची-ऊंची इमारतों वाले इलाकों में तापमान ज्यादा दर्ज होता है। तकनीकी भाषा में इसे 'अर्बन हीट आईलैंड इफैक्ट' कहा जाता है। पेड़-पौधों की कमी, अधिक शहरीकरण तथा कंक्रीट से अधिक निर्माण इत्यादि विविध कारणों से शहर ज्यादा तप रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह शहरों में निरन्तर बढ़ता जनसंख्या घनत्व भी है। जनसंख्या का घनत्व बढ़ते जाने से हरियाली नष्ट हो रही है और शहरों में हरे-भरे प्राकृतिक क्षेत्रों को भी सीमेंट तथा कंक्रीट के तपते जंगलों में तब्दील किया जा रहा है। दुनियाभर में विभिन्न शोधों के आधार पर वैज्ञानिक जलवायु संकट को ही लू के लिए जिम्मेदार मान रहे है, जिनका कहना है कि शहरीकरण तथा जनसंख्या घनत्व इसमें बड़ा योगदान देते हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के मुताबिक लू से अर्थव्यवस्था को चौतरफा नुकसान होता है। डब्ल्यूएमओ का कहना है कि बढ़ते तापमान का अर्थ हीट वेव का बढ़ना, बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ का पिघलना, समुद्र जलस्तर का बढ़ना तथा मौसम की चरम घटनाओं का और ज्यादा विनाशकारी होना है, जिसका सीधा प्रभाव पर्यावरण, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास पर पड़ेगा। इतिहास के सबसे गर्म वर्षों में लगभग सभी साल पिछले तथा इस दशक से ही रहे हैं। ब्रिटिश मौसम कार्यालय के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा है कि यदि जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा होता तो ऐसा चरम तापमान प्रत्येक 312 वर्षों में एक बार ही देखने को मिलता। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने भारत और पाकिस्तान में हर तीन साल बाद प्रचण्ड लू की आशंका जताते हुए दावा किया कि जलवायु परिवर्तन गर्मी की तीव्रता को जिस तेजी से बढ़ा रहा है, उससे इन क्षेत्रों के लोगों को आने वाले वर्षों में सौ गुना ज्यादा लू के थपेड़े झेलने पड़ सकते हैं।

योगेश कुमार गोयल

बहरहाल, अत्यधिक तापमान से जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य प्रणालियों की चिंता बढ़ जाती है, वहीं हीट वेव का श्रमिकों की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे देश की समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अत्यधिक गर्मी के कारण करीब 101 अरब घंटे खो देता है, जो पूरी दुनिया में सर्वाधिक है और 3.5 करोड़ लोगों द्वारा एक वर्ष में 8 घंटे कार्य करने वाले लोगों द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। आईएलओ की रिपोर्ट में भीषण गर्मी तथा लू के कारण 2030 तक दुनियाभर में अर्थव्यवस्था को 4.2 ट्रिलियन डॉलर की क्षति का अनुमान लगाया गया है। भारत के संदर्भ में इम्पीरियल कॉलेज में जलवायु विज्ञान के सीनियर लेक्चरर डॉ. फ्रेडरिक औटो कहते हैं कि भारत में मौजूदा गर्म हवाओं का एक बड़ा कारण कोयला तथा अन्य जीवाश्म ईंधन का जलाया जाना है और जब तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बंद नहीं होगा, तब तक भारत तथा अन्य स्थानों पर हीट वेव और भी गर्म व खतरनाक होती जाएगी। इन घातक स्थितियों से बचने के लिए जलवायु संकट से निपटने के अन्य उपायों के अलावा प्राकृतिक जंगलों के संरक्षण तथा आवासीय इलाकों में भी हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान को भी बढ़ावा देना होगा।

मां वाग्देवी के आंगन ऐतिहासिक भोजशाला में श्रद्धालुओं ने किया सत्याग्रह

माही की गुनी, धार।

धार की ऐतिहासिक भोजशाला में अब प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वाग्देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंगलवार को होने वाला नियमित सत्याग्रह इस बार विशेष आस्था और उत्साह के बीच संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां वाग्देवी की स्तुति की और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे पूरी भोजशाला भक्तिमय माहौल से गूंज उठी। भोजशाला आंदोलन में मार्गदर्शन देने वाले काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगदुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वतीजी महाराज और हिंदू महासभा के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर भी पहुंचे।

नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि अब मां वाग्देवी का मंदिर 365 दिनों तक हिंदुओं के लिए खुल गया है। यहां प्रतिदिन पूजन-अर्चन होगा। उन्होंने कहा कि लंदन के संग्रहालय में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को भी यहां विराजित किया जाएगा। यदि कोई अड़चन आती है तो शुद्ध ग्रेनाइट संगमरमर की प्रतिमा बनाकर स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भोजशाला का खोया हुआ मान, सम्मान और स्वाभिमान पुनः गौरव के साथ स्थापित होगा।

पत्थर और स्तंभ बता रहे भोजशाला का इतिहास

शंकराचार्य ने कहा कि, भोजशाला में मौजूद दीवारों के पत्थर, स्तंभ और शिल्प स्वयं इस बात के प्रमाण हैं कि यह मां वाग्देवी का स्थान रहा है। 64 योगिनियों के उल्लेख और यहां की कलाकृतियां भी इसकी पहचान को स्पष्ट करती हैं। उन्होंने कहा कि यह हिंदुओं का स्थान था, आज है और हमेशा रहेगा।

फिर से बने शिक्षा का केंद्र

शंकराचार्य ने कहा कि भोजशाला केवल मंदिर नहीं, बल्कि प्राचीन पाठशाला भी थी। यहां गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। नवग्रह, व्याकरण, साहित्य और न्याय दर्शन जैसे विषयों का अध्ययन यहां होता था। उन्होंने कहा कि भोजशाला को दोबारा शिक्षा का केंद्र बनाया जाना चाहिए, जहां सभी समाज के बच्चे शिक्षा प्राप्त करें और सरस्वती साधना के माध्यम से आइएएस, आइपीएस, इंजीनियर और डाक्टर बनें।

हाईकोर्ट के फैसले को बताया सत्य की जीत

शंकराचार्य ने कहा कि भोजशाला मालवा की आस्था और श्रद्धा की पहचान है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सबूतों और वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर फैसला सुनाया। यहां के स्तंभ, शिलालेख और कलाकृतियां स्वयं बता रही हैं कि यह मां वाग्देवी का मंदिर है। यह सत्य की जीत है।

स्वदेशी अपनाने और गोपालन का दिया संदेश

शंकराचार्य ने उपस्थित भक्तों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया और कहा कि विदेशी सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि विदेशी सामग्री का उपयोग करेंगे तो हमारा पैसा विदेश जाएगा और विदेशी देश मानवता के नाम पर वही धन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को देंगे। पाकिस्तान वह धन आतंकवादियों को देगा, फिर आतंकवादी कश्मीर यात्रा पर जाने वाले हिंदुओं को जाति-धर्म पूछकर गोली मारेंगे। इसलिए हमें स्वदेशी का उपयोग करना चाहिए। साथ ही पौधारोपण भी करना चाहिए। इसके अलावा हर घर में एक-एक गोमाता का पालन भी होना चाहिए। इनके साथ पूर्व में राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त पंडित योगेंद्र महंत और सचिव प्रिंसिपल टोंगिया भी मौजूद थे। इस अवसर पर भोज उत्सव समिति के गोपाल शर्मा, विश्वास पांडेय, हेमंत दौराया और सुमित चौधरी ने मां वाग्देवी का चित्र भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान किया।

ऊंची पहाड़ी पर स्थित बाबाघड़ा जल सोते की, की सफाई

माही की गूंज, आलीराजपुर।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद नवांकुर संस्था सोरवा सेक्टर द्वारा ग्राम कालीबेल के वेजलिया फलिया के घने जंगल में पेड़ो के झुरमुट व पहाड़ियों की चोटी पर स्थित प्राचीन व प्रसिद्ध बाबाघड़ा ऐतिहासिक वृक्ष जल सोता कुंड परिसर की ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सहयोग से साफसफाई कर बाबाघड़ा वृक्ष का पूजन अर्चन कर प्रकृति का जयघोष किया गया। ग्राम की सड़क के किनारे से करीब 750 मीटर ऊंची पथरीली चट्टानों के रास्ते पहाड़ी पर स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक गुलर के वृक्ष की जड़ों से निरंतर निकलते पानी के सोते से बहता जल इतनी ऊंचाई पर अपनी आश्चर्यजनक उपस्थिति दर्शाता है। वन्य क्षेत्र में मौजूद इस सोते के जल को जंगली जानवरों द्वारा पेयजल हेतु उपयोग में लिया जाता है इसीलिए वन विभाग ने यहां पर एक कुंडी बना रखी है परन्तु इस कुंडी के रखरखाव के अभाव में इसमें बड़ी मात्रा में मिट्टी की गाद, पेड़ो के पत्ते व कचरा जमा हो गया था। इसे ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सहयोगियों के जरिए साफ किया गया। साथ ही इस वृक्ष जल सोते के दोनों ओर स्थित मिट्टी का कीचड़, पेड़पत्र आदि कूड़ा करकट की सफाई भी की गई। इस अवसर पर उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता व एडवोकेट सुधीर जैन ने ग्रामवासियों को गंगादशहरा के पौराणिक महत्व को बताते हुए उन्हें जलगंगा संवर्धन अभियान की जानकारी दी। साथ ही ग्रामवासियों को अपने स्तर पर विविध रूप में जल संरक्षण किए जाने हेतु प्रेरित भी किया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद कट्ठीवाड़ा के विकासखंड समन्वयक नगरिया सस्तीया ने ग्राम में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति द्वारा अन्य आयोजित किए वाले कार्यक्रमों के बारे में समझाया। आखिर में ग्रामवासियों को जल स्त्रोतों द्वारा जल संरक्षण के संकल्प की शपथ सुधीर जैन ने दिलाई। जल स्त्रोत सोते की पूजन विधि ग्राम के चमचिया भगत ने की। ग्रामवासियों ने बताया कि, इस सोते से जंगली जानवरों जैसे भालू, लकड़बग्घा, सियार, मोर, तेंदुआ के साथ ही पक्षियों गौरैया, टिटहरी, नीलकंठ, उल्लू सहित बंदरों के पेयजल हेतु बहुत ही उपयोगी है। इस अवसर पर ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति कालीबेल के अध्यक्ष फत्तूसिंह डावर सहित ग्रामवासी बड़ी संख्या में मौजूद थे।

डीसीडीसी बैठक आयोजित

माही की गूंज, अलीराजपुर।

संयुक्त कलेक्टर मनोज गरवाल की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के जनसुनवाई सभाकक्ष में डीसीडीसी बैठक आयोजित की गई। बैठक में ÷सहकारिता से समृद्धि÷ योजना अंतर्गत विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना अंतर्गत कड्डीवाड़ा के सोरवा एवं सोण्डवा के छकतला में बी-पैक्स समितियों हेतु 500-500 एमटी क्षमता के गोदाम निर्माण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बी-पैक्स डाबड़ी में भूमि उपलब्ध नहीं होने से बड़ी खट्टाली समिति का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। बैठक में 26 बी-पैक्स समितियों में नए सदस्य बनाने की प्रगति की समीक्षा भी की गई। 5 हजार सदस्य बनाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 3196 सदस्य बनाए गए हैं। अधिकारियों को लक्ष्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत, सहकारिता, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, बैंक एवं नाबार्ड सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उक्त जानकारी उपायुक्त सहकारिता जिला आलीराजपुर द्वारा दी गई।

सहायक प्राध्यापक 50 हजार की रिश्वत लेते किया रंगे हाथ गिरफ्तार

माही की गूंज, धार/धामनोद।

इंदौर लोकायुक्त टीम ने बुधवार दोपहर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडलेश्वर शासकीय महाविद्यालय में पदस्थ सहायक प्राध्यापक आत्माराम सोलंकी को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई नेशनल हाईवे स्थित दुधी बायपास चौराहे के पास की गई। लोकायुक्त डीएसपी ने बताया कि आरोपित आत्माराम पुत्र सिरदार सोलंकी शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर जिला खरगोन में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ है। आरोपित को आवेदक से रिश्वत की राशि लेते हुए ट्रैप किया गया।

पत्नी की पोस्टिंग के नाम पर मांगी थी रिश्वत

आवेदक मनोज वास्केल निवासी यशवंत नगर मानपुर जिला इंदौर ने पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त इंदौर राजेश सहाय को शिकायत की थी। इसमें बताया गया कि उनकी पत्नी उर्मिला वास्केल का चयन पीएससी के माध्यम से सहायक प्राध्यापक पद पर हुआ था। शिकायत के अनुसार आरोपित आत्माराम सोलंकी लगातार फोन कर चार लाख रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था। आरोपित का कहना था कि उसी ने उर्मिला वास्केल की पोस्टिंग मंदसौर जिले के दलौदा से शासकीय महाविद्यालय धार में करवाई है, जो उनके निवास मानपुर के नजदीक है। आवेदक ने शिकायत में यह भी बताया कि आरोपित पहले ही एक लाख रुपये ले चुका था और शेष तीन लाख रुपये की मांग कर रहा था।

सत्यापन के बाद बिछाया जाल

लोकायुक्त टीम द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद आरोपित और आवेदक के बीच शेष राशि में से 50 हजार देने की सहमति बनी। लोकायुक्त ने ट्रैप दल गठित कर कार्रवाई की योजना बनाई। आरोपित ने रिश्वत की राशि लेने के लिए आवेदक को नेशनल हाईवे बायपास स्थित मधुबन ढाबे पर बुलाया था। यहां पहले से तैनात लोकायुक्त टीम ने घेराबंदी कर आरोपित को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक सुनील तालान, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक विवेक मिश्रा, आरक्षक विजय कुमार, कमलेश परिहार, रामेश्वर निगवाल, आशीष नायडू एवं प्रभात मोरे शामिल रहे।

रात में डाक्टर गायब, एक्सरे मशीन बंद, पेयजल संकट से मरीज परेशान

माही की गूंज, धार/तिरला।

स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इन दिनों पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही हैं। अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण मरीजों और ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है।

ग्रामीणों का आरोप है कि, रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान अस्पताल में डाक्टर समय पर उपलब्ध नहीं रहते। ऐसे में रात के समय उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों को इधर-उधर भटकना पड़ता है। कई गंभीर मरीजों को मजबूरी में धार रेफर होना पड़ता है। समय पर उपचार नहीं मिलने से मरीजों और उनके स्वजन में चिंता और असंतोष का माहौल बना रहता है।

गर्मी में पेयजल संकट, आरओ मशीन दे रही गर्म पानी अस्पताल में पेयजल व्यवस्था भी बदहाल बनी हुई है। परिसर में लगी आरओ मशीन से ठंडे पानी के बजाय गर्म पानी निकल रहा है, जिससे भीषण गर्मी में मरीजों और उनके स्वजन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल में स्वच्छ और ठंडे पेयजल तक की समुचित व्यवस्था नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

उधर, अस्पताल परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। परिसर में कुछ लोगों द्वारा उपले थोपे जाने से गंदगी फैल रही है और स्वच्छता प्रभावित हो रही है। जगह-जगह फैली गंदगी के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

वर्षों से बंद पड़ी एक्सरे मशीन

अस्पताल में लगी एक्सरे मशीन कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है। इसके चलते मरीजों को छोटी-छोटी जांचों के लिए निजी अस्पतालों या जिला अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि शासन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े-बड़े दावे करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बेहद खराब हैं। क्षेत्रवासियों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से अस्पताल में नियमित डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बंद पड़ी एक्सरे मशीन को शीघ्र चालू कराने, पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है।

झाड़ियों में मिला था मासूम, 36 दिन तक नर्सों ने मां बनकर गोदी में खिलाया

माही की गूंज, धार।

21 अप्रैल की सुबह ग्राम पंचायत चिकटियावड़ क्षेत्र में ओंकारेश्वर परियोजना की नहर किनारे झाड़ियों के पास जीवित अवस्था में मिले नवजात को शायद नई जिंदगी मिलनी ही थी। रोते हुए उस मासूम को जब जिला अस्पताल धार लाया गया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले 36 दिनों में अस्पताल का पूरा स्टाफ उसके लिए परिवार बन जाएगा।

जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती इस नवजात की नर्सों ने मां की तरह देखभाल की। जब भी मासूम रोता, नर्सें उसे गोद में लेकर चुप करातीं, प्यार से दुलारतीं और समय पर दूध पिलातीं। दिन-रात उसकी निगरानी की गई। अस्पताल स्टाफ का स्नेह और समुचित उपचार ही था कि नवजात धीरे-धीरे स्वस्थ होता चला गया।

बच्चे की हर धड़कन पर रखी नजर

अस्पताल के एसएनसीयू में 36 दिनों तक नवजात का विशेष उपचार चला। डाक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी। संक्रमण से बचाव से लेकर पोषण तक हर पहलू का ध्यान रखा गया। अस्पताल स्टाफ ने उसे सिर्फ मरीज नहीं, बल्कि अपने बच्चे की तरह संभाला।

पूरी तरह स्वस्थ होने पर भेजा इंदौर

मंगलवार को ड्यूटी डाक्टर डॉ. प्रियंका वर्मा की उपस्थिति में नवजात को पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद संजीवनी सेवा संगम शिशुगृह इंदौर भेजा गया। इस दौरान बाल संरक्षण अधिकारी बलराम ठाकुर, बाल कल्याण समिति सदस्य प्रेमसिंह डोडिया, बाल संरक्षण अधिकारी करण भंवर सहित अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा।

जिला स्तरीय ग्राम एवं नगर रक्षा समिति सम्मेलन

माही की गूंज, आलीराजपुर।

पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह द्वारा अनुभाग आलीराजपुर और जोबट के अंतर्गत आने वाले थानों के सक्रिय ग्राम एवं नगर रक्षा समिति के सदस्यों का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमे अनुभाग जोबट, आलीराजपुर के लगभग 80 सदस्य उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक द्वारा सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम एवं नगर रक्षा समिति के सदस्य हमारे आँख, कान हे जिले के हर गांव फलिया तक इनकी उपस्थिति होने से हमे हर गाँव और फलिया के सामाजिक समीकरण और वहाँ की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होने पर तत्काल सर्वप्रथम हमारे सदस्य वहाँ उपस्थित होकर पुलिस को सहयोग करने से अन्य लोगों में भी जागरूकता आती है एवं पुलिस सहयोगीं बनने की प्रेरणा लोगो को मिलती है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर क्राइम अपराध, महिला संबंधी अपराध, और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान में भागीदार बनने की अपील करते हुए सभी सदस्यों को आने वाले सिंहस्थ जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटियों के लिए भी तैयार रहने का आव्हान किया।

पश्चात आलीराजपुर एसडीओपी अश्विनी कुमार द्वारा सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्हें एक्सीडेंट, आगजनी तथा डूब क्षेत्र में बढ़चढ़कर सहायता प्रदान करने की बात कही और उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्यो की उदाहरणों सहित प्रशंसा की गई।

कार्यवाहक निरीक्षक श्री विजय देवड़ा द्वारा बताया गया कि आगामी सिंहस्थ का प्रशिक्षण प्राप्त किया जाकर आपको सिंहस्थ की तैयारियों हेतु उज्जैन के क्षेत्र, घाटों ,शाही स्नान पर अतिरिक्त भीड़ प्रबंधन हेतु विशेष अभियान चलाकर प्रशिक्षित किया जाएगा जिसके लिए स्वेच्छा से भाग लेकर ड्यूटी हेतु तैयार रहने हेतु बताया गया। अंत में रक्षित निरीक्षक इनोद रंधावा द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

हरियाली कटी, तपन बढ़ी...

माही की गूंज, धार/बदनावर।

पौधे लगाना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, इन पौधों को पांच वर्षों तक सुरक्षित रखने, सिंचाई करने और वन विभाग की निगरानी में उनका संरक्षण करने का भी स्पष्ट प्रविधान है। इसके बावजूद बदनावर क्षेत्र में बने कई मार्ग इन नियमों की हकीकत बयान कर रहे हैं।

इस बार मालवा क्षेत्र में गर्मी ने पिछले कई वर्षों के रिकार्ड तोड़ दिए हैं। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और हालात ऐसे बन गए हैं कि कभी अपनी शीतल आबोहवा के लिए पहचाना जाने वाला मालवा अब निमाड़ क्षेत्र से भी अधिक तपता नजर आ रहा है। दोपहर के समय सड़कें सुनसान हो जाती हैं, खेतों में काम करने वाले किसान छांव तलाशते दिखाई देते हैं और शहरों से लेकर गांवों तक हर व्यक्ति भीषण गर्मी से परेशान हैं। मालवा की ठंडी फिजा पर विकास की गर्म मार पड़ रही है।

पर्यावरण प्रेमियों और विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी है। पिछले डेढ़ दशक में क्षेत्र में सड़कों और फोरलेन मार्गों का तेजी से विस्तार हुआ, लेकिन इसके समानांतर हरियाली बढ़ाने और वृक्ष संरक्षण की दिशा में गंभीर प्रयास दिखाई नहीं दिए। यही वजह है कि मालवा का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले बदनावर में भी गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है।

फोरलेन बने, छांव हुई गायब

क्षेत्र से गुजरने वाले प्रमुख फोरलेन मार्गों पर हरियाली का अभाव साफ नजर आता है। राष्ट्रीय नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण के दौरान काटे गए प्रत्येक पेड़ के बदले 10 से 20 नए

खासकर लेबड़-नयागांव फोरलेन पर 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क किनारे ऐसे घने और छायादार वृक्ष बहुत कम दिखाई देते हैं, जहां राहगीर कुछ पल राहत महसूस कर सके। उज्जैन-बदनावर फोरलेन की स्थिति भी अलग नहीं है। एक वर्ष पूर्व तैयार हुए इस मार्ग पर लगाए गए पौधों में से कई सूखने लगे हैं, जबकि जो बचे हैं उन्हें बड़े वृक्ष बनने में अभी वर्षों लगेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और चिंताजनक है। सातरूण्डा-तिलगारा, जाबड़ा, कोद-बदनावर और कोद-भैंसोला मार्ग जैसे उदाहरण बताते हैं कि सड़क निर्माण के दौरान काटे गए वृक्षों की भरपाई आज तक धरातल पर नजर नहीं आती। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब नियम स्पष्ट हैं तो उनके पालन को लेकर जिम्मेदार विभाग और एजेंसियां आखिर कितनी गंभीर है।

13 हजार पेड़ों की कटाई, हरियाली अधूरी

साल 2008 में महू-नीमच मार्ग चौड़ीकरण के दौरान लगभग 13 हजार पुराने वृक्ष काटे गए थे। इसके बदले तीन गुना करीब 39 हजार पौधे लगाने का अनुबंध किया गया। वन विकास निगम खंडवा के साथ 50 हजार पौधे लगाने का समझौता भी हुआ। 131 किलोमीटर लंबे मार्ग में 125 किलोमीटर हिस्से में पौधारोपण किया गया, लेकिन उचित देखरेख और सिंचाई के अभाव में अधिकांश पौधे बड़े वृक्ष नहीं बन सके। फोरलेन किनारे करंज, शीशम, केसिया सामिया, सप्तवर्णी, कचनार, अशोक और गुलमोहर जैसी प्रजातियां लगाई गईं, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें पर्याप्त संख्या में ऐसे भारतीय और छायादार वृक्ष शामिल नहीं थे, जो लंबे समय तक टिकाऊ साबित होते। कई पौधे कमजोर जड़ों के कारण आंधी-तूफान में गिर जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।

भारतीय प्रजातियों की जरूरत

पर्यावरण प्रेमियों का मानना है कि सड़क किनारे नीम, पीपल, अर्जुन, पाकड़, अमलतास, आंवला और कचनार जैसे भारतीय प्रजाति के वृक्ष लगाए जाने चाहिए। ये वृक्ष न केवल अधिक छायादार होते हैं, बल्कि उनकी जड़ें भी मजबूत होती हैं और वे वर्षों तक पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल पौधे लगाने से पर्यावरण संरक्षण नहीं होता, बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

आज कई परियोजनाओं में पौधारोपण केवल आंकड़ों तक सीमित रह जाता है। फोटो खिंचते हैं, रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही स्थान फिर सूने नजर आते हैं। नया फोरलेन और नई चिंताअब बदनावर से थांदला-टिमरवानी तक बनने वाला नया फोरलेन मार्ग भी पर्यावरणीय चिंता का विषय बन गया है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ने वाले इस लगभग 89 किलोमीटर लंबे मार्ग पर करीब 1800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एजेंसी तय हो चुकी है और मुआवजा प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी दिनों में इस मार्ग की जद में आने वाले हजारों पुराने वृक्षों की कटाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार भी हरियाली केवल कागजों में सिमट कर रह जाएगी या वास्तव में वृक्षों का संरक्षण और प्रभावी पुनर्वनीकरण किया जाएगा?

क्या कहते हैं नियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

सड़क निर्माण के लिए काटे जाने वाले प्रत्येक पेड़ के बदले 10 से 20 नए पौधे लगाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है। नियमानुसार केवल पौधारोपण करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इन पौधों के संरक्षण, सिंचाई और देखरेख की जिम्मेदारी भी निर्माण एजेंसी की होती है। सामान्यतः तीन से पांच वर्षों तक वन विभाग की निगरानी में पौधों को जीवित रखना अनिवार्य रहता है। नियमों के मुताबिक अब पुराने और विशाल वृक्षों की भरपाई के लिए छोटे पौधों के बजाय कम से कम छह फीट ऊंचे पौधे लगाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं जहां संभव हो, वहां स्वस्थ पेड़ों को काटने के बजाय आधुनिक मशीनों की सहायता से जड़ सहित दूसरी जगह स्थानांतरित करने का प्रविधान भी किया गया है, ताकि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संतुलन भी बना रहे।

अब स्वच्छता सर्वेक्षण मं नगरपालिका की वाल पेंटिंग से पार पाने की फिसड्डी कवायद

जमीनी स्तर पर नगर में सफाई व्यवस्था राम भरोसे, बदबूदार व कचरे से पटे तालाब की स्थिति बता रही असल कहानी

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मिल मंसुरी

झाबुआ जिला मुख्यालय की हमेशा कर्जे में डूबी रहने वाली नगरपालिका इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रेंक के लिए दीवारों पर पेंटिग से पार पाना चाहती है। जबकि नगर की सफाई व्यवस्था और गंदे तालाब उसे मुंह चिढ़ाकर पार ना हो पाने की चुनौतियां देते दिखाई दे रहे है। मगर कहते है ना कि, पेंट कोई सा भी लगाओ दीवारें कभी बोलती नहीं है, मगर हां दीवारों के कान जरूर होते है। जिस तरह नगरपालिका, शहर में जगह-जगह खाली पड़ी दीवारों को रंगने में पैसा खर्च कर रही है अगर वही पैसा सफाई व्यवस्था या तालाबों की सफाई में खर्च करती तो शायद परिणाम कुछ ओर होते। मगर नगरपालिका में बैठे जिम्मेदारों और भामाशाहों को लगता है कि, दीवारों को पोत देने से दीवारें बोल उठेंगी। दीवारें बोले या ना बोले मगर नगर में सढ़ांध मारते तालाब बहुत कुछ कह रहे है। नगर का छोटा तालाब जो करोड़ों के भ्रष्टाचार के बावजूद भी अपनी दुदर्शा पर आंसू बहा रहा है। वह अब भी गंदे नाले में दिन ब दिन तब्दील होता जा रहा है। शहर के दुषित होते इन तालाबों पर नगरपालिका सिर्फ फव्वारें लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री में लगी हुई है। भला यह क्या लॉजिक हुआ कि, गंदे पानी में फव्वारा लगाने से पानी साफ हो सकता है...? जो फव्वारे गंदे तालाबों में नगरपालिका ने पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने और पानी को साफ करने के लिए लगाए थे वे महज कुछ ही दिन अपना झांकी मंडप दिखा पाए। विडम्बना यह कि कई बीघा लंबे-चौड़े तालाबों में महज एक-एक फव्वारा ही लगाया गया। यह कैसे संभव है कि इतने बड़े तालाब में एक फव्वारा पानी के ऑक्सीजल लेवल को बढ़ा देगा या पानी को साफ कर देगा...? हालांकि इन फव्वारों में लगी लाइटिंग जरूर लोगों को आकर्षित कर रही थी। मगर महज कुछ दिनों में इन फव्वारों की हवा निकल गई और अब यह फव्वारे कभी बंद तो कभी चालू तो कभी फव्वारे की लाइट बंद तो कभी चालू वाली स्थिति बनी हुई है।

लोग कहते है कि, यह नगरपालिका के माथा उतारनी के चौचले है। छोटे तालाब में लगा फव्वारा तो महज एक या दो दिन चल पाया। उसके बाद से ही इस तालाब में लगे फव्वारे बंद पड़े है। तालाब पूरी तरह से सेप्टिक टेंक में तब्दील हो चुका है और इससे भयानक बदबू आती है जो रहवासियों और राहगीरों का जीना दुर्भर कर रही है। तालाब के आसपास भरपूर अतिक्रमण फैल चुका है जिसे हटाने में नगरपालिका हमेशा ही नाकाम साबित हुई है। इस तालाब के सौंदर्यीकरण में गढ़ी गई भ्रष्टाचार की गाथा पूरे शहरवासियों को मालूम है। जिसमें कलेक्टर जैसे अधिकारियों तक के नाम जांच में उजागर हुए है। ऐसी स्थिति में नगरपालिका इन तालाबों में फालतू के फव्वारें लगाकर क्या साबित करना चाहती है। हालांकि बताने वाले बताते है कि, कलेक्टर साहब आए थे निरीक्षण करने और वे ही तालाब के आसपास का अतिक्रमण हटाने व तालाब में फव्वारे लगाने के निर्देश दे गए थे। तो नगरपालिका ने भी आव देखा ना ताव बिना किसी मतलब के ही तालाबों में एक-एक फव्वारे डाल दिए।

पिछले दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की टीम झाबुआ दौरे पर आई थी। नगरपालिका ने उन्हे सावन का अंधा समझ कर सबकुछ हरा-हरा दिखाने की कोशिश भी की थी, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण की केंद्रीय टीम नगर में भ्रमण के दौरान छोटे तालाब पर पहुंच गई और नगरपालिका की सारी पोल खुल गई। हालांकि नगरपालिका ने नगर की रंगी पुती दीवारे दिखाकर टीम को प्रभावित करने के भरसक प्रयास किए थे लेकिन नगर के गंदे, बदबूदार और अतिक्रमणयुक्त तालाबों ने नगरपालिका के मुंह पर कालिख पोतकर रख दी। टीम ने स्थिति को देखकर काफी असंतुष्टी जाहिर की। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम जो अपना काम कर चुकी, लेकिन नगरपालिका अब सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटती नजर आ रही है। कलेक्टर के निर्देश के बाद नगरपालिका प्रशासन एक्शन मोड में आने का दिखावा कर रहा है। तालाब के आसपास अतिक्रणकर्ताओं पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

अब सवाल यह है कि, स्वच्छता सर्वेक्षण में नगरपालिका जिस वाल पेंटिग के जरिए पार पाना चाहती थी वह अब कितना काम आएगी...? और नगरपालिका के स्वच्छता सर्वेक्षण का भांडा फोड़ने वाले तालाबों का क्या होगा...? या फिर यही गंदे, बदबूदार तालाब झाबुआ नगरपालिका को स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिग लिस्ट से बाहर कर देंगे...? या फिर नगरपालिका में बैठे जिम्मेदार और भामाशाह कोई गोटी ऐसी फैकेंगे कि नगरपालिका स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंक में अग्रणी बन जाए...?

खैर जो भी हो लेकिन रंगी पुती दीवारे कभी बोलती नहीं है, और कई बीघा में फैले तालाब में एक-एक फव्वारे लगाकर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना और पानी साफ करना सूरज को दिया दिखाने जैसा ही लगता है।

विशेष जनसुनवाई में आ रही शिकायतें ही माही की गूंज में छपे समाचारों की करती है पुष्टि

माही की गूंज, खवासा। सुनिल सोंलकी

तलावड़ा में पंचायत स्तर पर जनसुनवाई।

क्षेत्र व जिले में जहां शासन व प्रशासन द्वारा सभी दूर हरा ही हरा होना बताया जाता है। वहीं दूसरी और माही की गूंज पूरी बेबाकी के साथ जिले व क्षेत्र का सच प्रकाशित करता रहा है जिसमें मूलभूत सुविधाओं से ही व्यक्ति वंचित है। स्वच्छता अभियान के तहत गांव-गांव में निजी व सार्वजनिक शौचालय हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला हो, मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों में अनियमित्ता व मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलना, घर-घर नल प्रतिदिन जल के तहत नल-जल योजना में किए गए कार्यों की अनियमित्ता व बनाई गई पानी की टंकियां अब भी शोपीस में दिखाई दे रही है। और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है आदि जमीनी स्तर पर इन समस्याओं को लेकर माही की गूंज प्रमुखता से समाचारों का संकलन कर प्रशासन, सरकार व विपक्ष के नुमाइंदों के सामने समस्याओं के समाधान के लिए लाता रहा है। लेकिन न ही सरकार व विपक्ष के नुमाइंदे इस और कोई ध्यान दे पा रहे हैं। साथ ही प्रशासनिक नुमाइंदे भी ऑफिस में बैठकर सभी दूर हरा-हरा होना बताकर अपने कार्य की इतिश्री कर रहे हैं।

वही जब सबसे दूर सबसे पहले अभियान के अंतर्गत जब प्रशासनिक नुमाइंदे पंचायती स्तर पर जनसुनवाई कर रहे हैं तो माही की गूंज में छपे तमाम समाचारों की पुष्टि करने वाली शिकायतें प्रशासन के सामने आ रही है और प्रशासन समस्याओं के निराकरण के निर्देश दे रही है। पर समस्याओं के निराकरण करने वाले ये निर्देश कितने सार्थक व प्रभावी होगें यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।

बता दे कि, क्षेत्र की सभी पंचायतो में 22 मई शुक्रवार को विशेष जनसुनवाई का आयोजन रखा। वही थांदला डिवीजन के एसडीएम भास्कर गाचले सहित अधीनस्थ अधिकारी जिले के अंतिम ग्राम पंचायत माही तट से सटी ग्राम पंचायत तलवाड़ा में जनसुनवाई ली। जिसमें मनरेगा, स्वास्थ्य, पेयजल, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन आदि समस्याओं को लेकर शिकायते सामने आई। तथा उक्त समस्याओं का प्रकाशन माही की गूंज हर समय करता रहा है। लेकिन प्रशासन इन समस्याओं को दूर करने के बजाय सरकारी आंकड़ों के घोड़े कागजों में ही दौड़ाते रहते हैं।

अगर प्रशासन निष्पक्ष व त्वरित कार्रवाई का आश्वासन तो हमेशा देती हैं लेकिन समाधान किसी का नहीं होता है। नतीजन यह कि, सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत आ रही शिकायते ही प्रशासन व सरकार की नाकामियों को उजागर करती है व माही की गूंज में जनहित में छपे तमाम समाचारों की पुष्टि करती है।

रतलाम-झाबुआ मार्ग पर बामनिया में बनेगा बाई पास

ठेकेदार ने छूटी हुई सड़क को बिना खोदे बना दी

माही की गूंज, पेटलावद।

एमपीआरडीसी विभाग के माध्यम से बन रहे रतलाम-झाबुआ मार्ग का निर्माण तेजी से चल रहा है। थांदला की ओर बनता आ रहा मार्ग बामनिया-खवासा के बीच निर्माण रोक कर सड़क निर्माण एजेंसी ने मार्ग का निर्माण लाड़की नदी के पास से शुरू कर दिया था। लगभग दो से तीन किलोमीटर का भाग निर्माण एजेंसी ने दोनो और से छोड़ दिया। जबकि बाकी के गावो में सड़क निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन बामनिया में ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। कुछ दिन पूर्व सड़क निर्माण एजेंसी ने खवासा घाटी से लेकर चित्तौड़ीरुंडी के बीच छोड़े कार्य को पुन शुरू कर दिया लेकिन निर्माण एजेंसी द्वारा रोड को बिना अर्थ वर्क किए केवल सड़क पर स्क्रैच कर डामरीकरण कर दिया गया, न ही रोड को खोदा गया न ही रोड को दस मीटर बनाया गया। एक दिन में ही निर्माण एजेंसी ने बचे हुए कार्य को आधे से ज्यादा निपटा दिया। इस प्रकार से अचानक हुए निर्माण के बाद ग्राम में चर्चा का विषय रहा कि आखिर ठेकेदार दूसरे गांव की तरह बामनिया में रोड छोटा क्यों बना रही है।

इस विषय में सहायक महाप्रबंधक रामगोपाल हटीला से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि, बामनिया में बाई पास बनना है जो कि गाइड लाइन के हिसाब से दस मीटर का बनाया जाएगा। बाकी बचे हुए हुए मार्ग को साढ़े पांच मीटर बनाया जा रहा है। बाईपास मार्ग को लेकर फिलहाल कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है कि, वो किस क्षेत्र से निकलेगा क्योंकि बामनिया में रेलवे लाइन जा रही है उस पर ओवर ब्रिज बनना है।

मजबूत निर्माण नहीं होने से जल्द खुदेगी सड़क

बाई पास के नाम पर एमपीआरडीसी विभाग ने सड़क निर्माण एजेंसी के साथ काम धकाऊ काम कर के इति श्री कर ली गई। बाई पास निर्माण को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है ओर इसका निर्माण भी अभी शुरू नहीं है। मार्ग के निर्माण के चलते ठेकेदार के भारी वाहन सहित इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अत्यधिक होती है। जिस प्रकार मार्ग की लिपा-पोती की गई है ये दो से तीन किलोमीटर का टुकड़ा जल्द ही जर्जर होना तय है। जिससे मार्ग से बाई पास बनने से पहले गुजरने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वही बाई पास बनने से बामनिया के आसपास जाने वालो के पास भी नई सड़क के नाम पर ये जर्जर सड़क का हिस्सा रह जाएगा।

ग्राम पंचायत बामनिया के उपसरपंच ने इस मामले में बताया कि, सड़क निर्माण एजेंसी ओर एमपीआरडीसी विभाग से चर्चा कर सड़क को नियमानुसार खुदाई कर मजबूत बनाने की मांग की जाएगी।

अंधेकत्ल का खुलासा पर अन्य अपराधी को बचाने का पुलिस पर आरोप

आरोपी की गैर मौजूदगी में घर आना-जाना बना मौत का कारण

माही की गूंज, करवड़। अरूण पाटीदार

करवड़ चौकी पर प्रदर्शन कर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते मृतक के परिजन ओर ग्रामीण।

फरियादी ईश्वर पारगी निवासी चंवरापाड़ा द्वारा बताया कि, उसका भाई शांतु पारगी दिनांक 17 मई को लापता हो गया है। काफी तलाश करने पर भी नहीं मिला। 18 मई को शांतु पारगी का शव बामनझीरी क्षेत्र से बरामद हुआ, जिसके चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। जिस पर से पुलिस ने मर्ग 35/2026 दर्ज कर जांच में लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 239/2026 धारा 103 (1) भारतीय न्याय संहिता का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन कर जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक घटना वाले दिन अपने मित्र दिनेश उर्फ दितिया मोरी निवासी चंवरापाड़ा के साथ देखा गया था। घटनास्थल से मिले शराब के क्वार्टर, पानी की बोतल एवं अन्य भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस का संदेह आरोपी पर गहराया। 23 मई को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी दिनेश मोरी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक उसकी गैरमौजूदगी में उसके घर आता-जाता था, जिससे वह नाराज रहता था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने शराब पार्टी के बहाने मृतक को सुनसान स्थान पर ले जाकर लोहे की टामी से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

हत्या के मामले का खुलासा तो पुलिस ने कर दिया लेकिन पुलिस की कार्यवाही से मृतक का परिवार संतुष्ट नहीं है। मृतक के परिवार सहित ग्रामीणजनों ने आरोपी के परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मिल कर हत्या को अंजाम देने का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों का कहना है कि, आरोपी का एक ओर अन्य भाई जिससे मृतक का काफी समय से विवाद चल रहा था और वो कई बार मृतक व उसके बेटे में से किसी भी एक को जान से मारने की धमकी दे चुका है और दो बार मामला करवड़ चौकी पर भी पहुंचा लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिससे आरोपियों को मौका मिला ओर उन्होंने मिल कर हत्या की घटना की है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि, घटना स्थल पर पुलिस, कुत्ता लेकर आई थी वो भी एक-एक कर तीनो आरोपियों के मकान में गया था और सबसे पहले उस व्यक्ति के मकान में गया जिससे पुराना विवाद चल रहा था। इसके बाद भी पुलिस ने दूसरे भाई जो मृतक के ही साथ रह कर करवड़ में हिमाली का कार्य करता था उसे आरोपी बना दिया। उधर पुलिस अभी भी मामले की जांच के दौरान आरोपी की संग्लिप्ता होने पर आरोपी बढ़ाने की बात की है।

धर्मांतरण के आरोप: होटल में मसीही आध्यात्मिक सम्मेलन में विवाद

बजरंग दल और पुलिस में हुई नोकझोंक

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम की होटल अजंता पैलेस में बुधवार दोपहर आयोजित मसीही आध्यात्मिक सम्मेलन 'जीवन दर्शन' को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर धर्मांतरण के आरोप लगाए। जिसके बाद मौके पर तनाव जेसी स्थिति बन गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी सीएसपी अजय सारवान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। विरोध प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के पदाधिकारी उस हॉल के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों ने विरोध स्वरूप परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने एहतियातन हॉल के मुख्य प्रवेश द्वार को नियंत्रण में ले लिया और आवाजाही पर रोक लगा दी।

पुलिस से धक्का-मुक्की

स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब कुछ बजरंग दल पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच बहस के बाद धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। पुलिस ने हस्तक्षेप कर कार्यकर्ताओं को बाहर किया और हालात पर नियंत्रण किया।

जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के मुताबिक, यह सम्मेलन यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल रतलाम और रतलाम पास्टर्स फेलोशिप के तत्वावधान में किया जा रहा था। कार्यक्रम स्थल पर दोनों संस्थाओं के बैनर भी लगे हुए थे। घटना के बाद पुलिस, सम्मेलन में मौजूद लोगों की पहचान और अन्य जानकारियां जाच में जुटा रही है। अधिकारियों द्वारा एक-एक व्यक्ति का नाम और विवरण दर्ज किया जा रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422